सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सफलता की ख़ुशी मनाना अच्छा है पर, उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना !

वर्ष 01, अंक 208, नई दिल्ली

मंगलवार, 10 अक्टूबर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

खत्म हुआ इंतजार, रैपिड रेल के शुभारंभ की तारीख आई सामने... पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा और जिलाधिकारी राकेश कुमार पांडे के अलावा अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थळ का निरीक्षण किया।

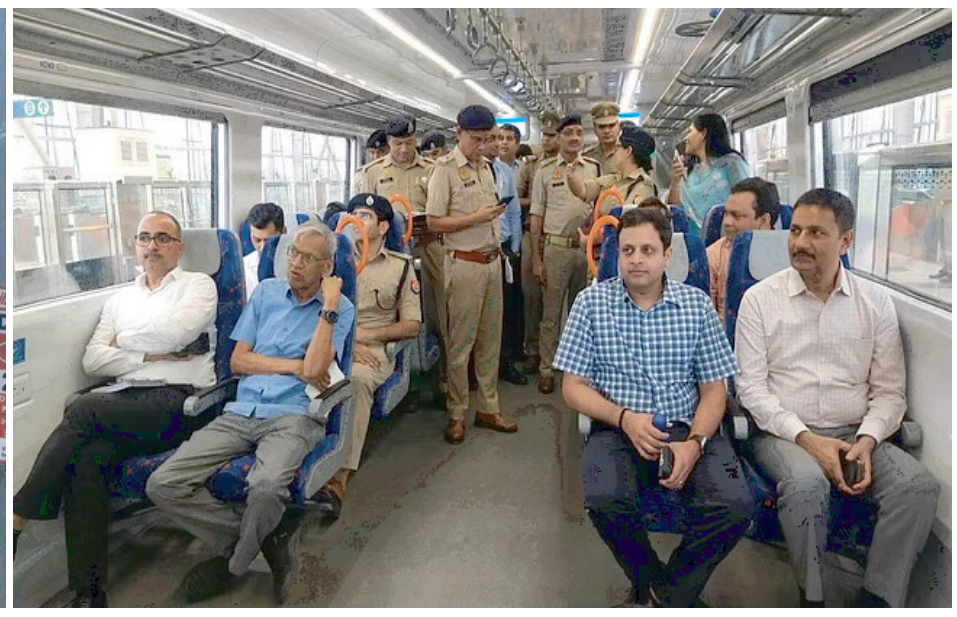

संजय बाटला, सम्पादक

कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार को पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा और जिलाधिकारी राकेश कुमार पांडे, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने तमाम अधिकारियों के साथ वसुंधरा स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

नई दिल्ली/गाजियाबाद। दिल्ली को पश्चिमी यूपी से जोड़ने वाली केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित परियोजना रैपिड रेल से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। रैपिड रेल के शुभारंभ से जुड़ीं तीन तारीख सामने आई हैं। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा और जिलाधिकारी राकेश कुमार पांडे के अलावा अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थळ का निरीक्षण किया।

राजधानी दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक जाने वाली देश की पहली हाई स्पीड रैपिड रेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्तूबर की संभावित 16, 17 या 18 तारीख को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार को पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा और जिलाधिकारी राकेश कुमार पांडे, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने तमाम अधिकारियों के साथ वसुंधरा स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

इस बीच पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने हाई स्पीड ट्रेन में बैठकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम बारीकियों को जाना। वसुंधरा सेक्टर-8 में कार्यक्रम स्थल को तैयार करने का काम जोरों पर शुरू हो गया है। मैदान के आसपास झुग्गी झोपड़ी और अन्य तरह के अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने एनसीआरटीसी के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित निर्देश दिए।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Fornt Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

बेकाबू डीटीसी बस ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर एक की मौत, ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी दिल्ली में बीती रात यानी 8 अक्टूबर को बेकाबू दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस ने दो ई-रिक्शा और एक फल के ठेले को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में 36 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत की सूचना है. साथ ही तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से आरोपी डीटीसी चालक फरार है. उसकी तलाश जारी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान आनंद के रूप में हुई है. घायलों की पहचान अली, समीर और आसिफ के रूप में हुई है. घायलों को इलाज अस्पताल में जारी है.

ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें कल्याणपुरी में एक डीटीसी बस द्वारा कुछ लोगों को टक्कर मारने से संबंधित एक पीसीआर कॉल मिली. पुलिस दल मौके पर पहुंचा और पाया कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हैं. चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया. प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

महिला और 2 बच्चों के शव बरामद

वहीं, साउथ वेस्ट दिल्ली के मुनिरका में 8 अक्टूबर को एक घर से एक महिला और उसके दो बच्चों के शव बरामद किए गए हैं. मृतकों की कलाइयों पर तेजधार हथियार से चोट के निशान भी मिले हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान वर्षा शर्मा और उनके चार एवं ढाई साल के दो बच्चों के रूप में हुई है. मृतक महिला एनसीबी में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी थीं. उनकी शादी 2017 में हुई थी.

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजकर 30 मिनट पर हमें सूचना मिली कि मुनिरका गांव स्थित एक घर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है. किशनगढ़ पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी. पुलिस को घर में महिला और उसके दो बच्चों के शव मिले तथा उनकी कलाइयों पर किसी तेजधार हथियार से चोट के निशान मिले हैं.

नवरात्र से स्मार्ट सफर का लुत्फ उठाएंगे शहरवासी, इलेक्ट्रिक बसों का किराया भी होगा सस्ता

जम्मू शहर वासियों का स्मार्ट सफर का इंतजार खत्म होने वाला है। 10 ई-बसों का ट्रायल पूरा हो चुका है। नवरात्र पर जम्मू और श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ई-बसों के संचालन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अन्य परिवहन के साधनों के मुकाबले किराया सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक बसें चलने से यातायात सुगम, प्रदूषण रहित होगा। इसके अलावा यात्रियों के लिए सफर सुविधाजनक हो जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी शहर में लंबे समय से ई-बसें चलाने की तैयारियां कर रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्तूबर 2021 में हुई बैठक में केंद्र इंडिया योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। टाटा कंपनी के साथ एक साल के अंदर बसें मिलने का करार हुआ था। इसके तहत 10 बसें स्मार्ट सिटी को मिल चुकी हैं। अन्य बसें अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मिलने की बात कही जा रही है। बसों का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। अब इन्हें आमजन के लिए सड़कों पर उतार दिया जाएगा। इस बारे में स्मार्ट सिटी के सीईओ एवं कमिश्नर नगर निगम राहुल यादव का कहना है कि ई-बसों का ट्रायल पूरा हो चुका है। बसों का किराया अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधनों से कम होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी संभावना है कि नवरात्र में बसों का संचालन शुरू हो जाए। बसों की खास बात यह है कि सुगम सड़कों पर 65 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। इसमें सीसीटीवी कैमरे, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन दरवाजे, प्राथमिक चिकित्सा और जीपीएस की व्यवस्था होगी। बैटरी एल-वन आयन फास्फेट, पावर स्टीयरिंग, पूर्णतया गीयरलेस व स्वचालित व्यवस्था है।

दिल्ली से वाराणसी जा रही बस एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटी, 35 यात्री घायल, 9 की हालत गंभीर

दिल्ली से वाराणसी जा रही एक बस रविवार रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई। बस में सवार करीब 35 लोग घायल हो गए। घायलों को फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है। गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया है। कई लोगों को फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है।

आगरा: दिल्ली से वाराणसी ले जा रही बस रविवार रात दुर्घटना ग्रस्त हो गई। बस में सवार 35 यात्री घायल हो गए। इनमें से 9 लोग गंभीर रुप से घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आगरा रेफर कर दिया है। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। 20 माइल स्टोन पर बस का टायर फट गया और डिवाइडर से टकरा कर बस पलट गई।

हादसा रविवार रात करीब 9.30 बजे हुआ। दिल्ली से यात्रियों को वाराणसी लेकर आ रही बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे स्थित फतेहाबाद थाना क्षेत्र के 20 माइल स्टोन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। थाना प्रभारी फतेहाबाद ने बताया कि बस में कुल 40 से 45 यात्री सवार थे। रविवार रात 20 माइल स्टोन पर अनाचक बस का आगे का टायर फट गया और बस अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बस में सवार करीब 35 लोग घायल हो गए। जिनमें 9 अधिक गंभीर रुप से घायल हुए हैं।

गंभीर घायलों को किया आगरा रेफर

थाना प्रभारी फतेहाबाद ने बताया कि घायलों को फतेहाबाद सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) पर पर भर्ती कराया है। इनमें से 9 लोग गंभीर रुम से घायल हो गए हैं। जिन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घायलों में ज्यादातर लोगों के फ्रैक्चर हुआ है। सभी का इलाज चल रहा है।

बंगलूरु, दिल्ली ट्रैफिक जाम को जल्द कह सकेंगे अलविदा? सरकार बना रही है यह बड़ी योजना

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। क्या बंगलूरु, दिल्ली में ट्रैफिक जाम जल्द ही अतीत की बात हो जाएगा? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बंगलूरु, जो ट्रैफिक जाम के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, और नई दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह योजना German Agency for International Cooperation (जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (DPIIT) द्वारा विकसित की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित योजना, जिसे आने वाले महीनों में लागू किया जाना है, सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक मल्टी-मॉडल परिवहन बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस योजना का एक प्रमुख पहलू यह है कि इसमें माल और यात्री परिवहन दोनों को मांग के रूप में माना जाएगा। वर्तमान में, शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ में माल यातायात का प्रमुख योगदान होने के बावजूद, ज्यादातर शहरी नियोजन पहल मुख्य रूप से यात्री आवाजाही पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, इस योजना का लाभ यह है कि इसे समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय अपनी विशिष्ट जरूरतों के मुताबिक इन मॉडलों को अपना सकते हैं।

कई शहरों में ट्रैफिक जाम एक लगातार समस्या है, और बंगलूरु की सड़कें हाल ही में तब सुर्खियां बनीं जब एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के शो के कारण बड़ी ट्रैफिक जाम हुई। इस समस्या से निपटने की कोशिश में, ज्यादातर शहरों ने नगरपालिका सीमा के भीतर ट्रकों और भारी-भरकम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, इन उपायों के बावजूद, बड़े

शहरों को माल और यात्री परिवहन दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

प्रस्तावित योजना में रेलवे स्टेशनों के पास भीड़भाड़ वाले इलाकों से यात्रियों और सामानों की आवाजाही पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो शहरों में महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र हैं। यह दिल्ली और बंगलूरु के सिटी मास्टर प्लान का पूरक होगा। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस समय दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2041 (एमपीडी-2041) और क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) को अंतिम रूप दे रहा है। इसी तरह, बंगलूरु विकास प्राधिकरण ने बेंगलूरु-2031 के लिए एक संशोधित मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

बुनियादी ढांचा विकास थिंक-टैंक इन्फ्राविजन फाउंडेशन के संस्थापक विनायक चटर्जी ने भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़कों पर कारों की संख्या कम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी में निवेश करने का सुझाव दिया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन से 10 मिनट से ज्यादा दूर न हो। चटर्जी ने प्रमुख शहरों में परिवहन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की भी सिफारिश की।

उन्होंने इन शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए भारत को नगरपालिका बॉन्ड का पता लगाने और पूंजी बाजार से धन जुटाने की जरूरत पर रोशनी डाली। चटर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि शहरों के शासन और प्रशासन में व्यापक सुधार जरूरी हैं, जिसमें डबल-एंट्री बहीखाता पद्धति, यूजर-पे चार्ज और बेहतर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जैसे उपाय शामिल हैं।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/ 25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारत में कैंसर से महिलाओं को मौत का खतरा ज्यादा

लैंसेट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जल्द करें 5 काम, बच सकेगी जान

लैंसेट की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भले ही पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन कैंसर होने पर महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है. इसकी वजह सही समय पर कैंसर का पता न लगना और इलाज की कमी है. आज आपको बताएंगे कि महिलाएं किन तरीकों से कैंसर का वक्त रहते पता लगा सकती हैं.

भारत में कैंसर से पीड़ित अधिकतर महिलाओं को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है. इसका खुलासा लैंसेट कमीशन की नई रिपोर्ट में हुआ है. इसके अनुसार भारतीय महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली लगभग 63% मौतों को स्क्रीनिंग और निदान के जरिए रोका जा सकता था. जबकि 37% मौतों को समय पर सही इलाज से रोका जा सकता था. देश में कैंसर देखभाल में लैंगिक असमानता (gender inequity) पर लैंसेट आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. इसमें कहा गया है कि भले ही पुरुषों में कैंसर का खतरा अधिक होता है, लेकिन महिलाओं में कैंसर के मामले और मृत्यु दर ज्यादा रहती है.

नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली लगभग 69 लाख मौतें रोकी जा सकती थीं और 40.3 लाख महिलाओं का इलाज किया जा सकता था. वैश्विक स्तर पर कैंसर के नए मामलों में 48% महिलाएं होती हैं और कैंसर से होने वाली मौतों में 44% महिलाएं शामिल हैं. ऐसा तब होता है, जब महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर व सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है और उसे इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है. चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाएं जानकारी के अभाव, फाइनेंशियल पावर और प्राइमरी सर्विसेज की उपलब्धता की कमी के कारण सही समय पर और उचित इलाज नहीं करवा पाती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहे महिलाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहती हों और समाज के किसी भी तबके से आती हों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जानकारी और निर्णय लेने की शक्ति की कमी होने की संभावना अधिक होती है.

नसों से बैड कोलेस्ट्रॉल निकाल देंगे ये 6 फूड आगे देखें...

इस बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट ?

नई दिल्ली एम्स के ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक शंकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कैंसर देखभाल में निश्चित रूप से जेंडर एक बड़ा फैक्टर होता है. गरीब महिलाओं को इस बारे में हेल्थकेयर को लेकर काफी कम जानकारी है. इसका असर महिलाओं पर पड़ता है. धूम्रपान और तंबाकू के संपर्क में आने वाले महिला और पुरुष दोनों को कुछ कैंसर का खतरा बराबर होता है, लेकिन महिलाओं का इलाज प्राथमिकता नहीं है. यही कारण है कि उनकी कंडीशन बदतर हो जाती है. कैंसर और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी के अलावा, सामाजिक बदलाव की भी जरूरत है. महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है. इन कैंसर को इलाज के जरिए रोका जा सकता है. हालांकि महिलाएं इन समस्याओं को लेकर पुरुष डॉक्टरों के पास जाने से झिझकती हैं या महिला डॉक्टर से प्राइवेट पार्ट की जांच करने से भी हिचकिचाती हैं, जिससे इलाज में देरी होती है.

महिलाएं करें 5 काम, कैंसर की होगी रोकथाम

– सभी महिलाओं को हर महीने अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करनी चाहिए और साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए.

– 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए साल में एक बार मैमोग्राफी (mammography) करवानी चाहिए.

– जिन महिलाओं को सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान ब्रेस्ट में किसी गांठ का पता चलता है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करा चाहिए.

– सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए 25 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं को पैप स्मीयर परीक्षण (pap smear test) करवाना चाहिए. – महिलाओं को मानव पैपिलोमा वायरस का पता लगाने के लिए हर 5 या 10 साल में एचपीवी परीक्षण (HPV test) करवाना चाहिए।

अनियमित पीरियड्स से हैं परेशान? इन 3 चीजों से बने आयुर्वेदिक चूर्ण का करें 12 सप्ताह तक सेवन, दूर होगी कई परेशानी

यदि आपका पीरियड्स बार-बार मिस हो रहा है या फिर ब्लीडिंग कम होती है, पेट में बहुत दर्द रहता है तो आप मेथी, अलसी के बीज और काले तिल से बने चूर्ण का सेवन करें. यह मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के साथ ही वेट लॉस, स्ट्रेस कम करने, नींद अच्छी लाने में भी कारगर है.

अक्सर कुछ महिलाओं को पीरियड्स सही समय पर नहीं आता है. इर्रेगुलर पीरियड्स या डिले पीरियड्स की समस्या से अधिकतर महिलाएं परेशान रहती हैं. यह समस्या बढ़ती उम्र में अधिक देखने को मिलता है. कई बार पीसीओडी और पीसीओएस से ग्रस्त महिलाओं में भी अनियमित मासिक धर्म की समस्या देखी जाती है. कुछ महिलाओं को पीरियड्स तो होता है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होती है. ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है और दो दिन के अंदर ही पीरियड्स खत्म भी हो जाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ महिलाएं या लड़कियां दवाओं का सेवन करती हैं. कई बार हॉर्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाता है. हॉर्मोनल पिल्स के सेवन से शारीरिक और मानसिक रूप से नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पिल्स की बजाय नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए. इनसे वजन भी नहीं बढ़ता है. महिलाओं में होने वाली मूड स्विंग, डिप्रेशन, इन्सोम्निया की समस्या भी नहीं होती है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. दीक्षा भावसार (Dr. Dixa Bhavsar) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने डिले और इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या को दूर करने का नेचुरल घरेलू नुस्खे के बारे में बताया है. उन्होंने एक चूर्ण के बारे में बताया है, जो पीरियड्स संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है. ये चूर्ण अलसी के बीज, मेथी के दाने और काली तिल को एक साथ पीसकर तैयार किया गया है.

अनियमित पीरियड्स की समस्या दूर करेगा ये नेचुरल उपाय

आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स, डिले पीरियड्स या फिर मासिक धर्म के दौरान कम ब्लीडिंग होने की समस्या है तो आप इस पाउडर का सेवन जरूर करें. इसके लिए आप रोस्ट की हुई काली तिल, मेथी के बीज और अलसी के बीज बराबर मात्रा में लें. इसे मिक्सी में डालकर पाउडर की तरह पीस लें. इसे सुबह के समय या फिर रात में सोने से पहले 1 छोटा चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं. इसे आप प्रतिदिन लगभग 12 सप्ताह यानी तीन महीने तक सेवन करें. आप इस चूर्ण का सेवन प्रत्येक महीने पीरियड्स होने के दूसरे दिन से लेकर आखिरी दिन तक कर सकती हैं. पीरियड्स समाप्त होते ही फिर से इसे खाना शुरू कर सकती हैं.

मेथी, अलसी, काले तिल से बना चूर्ण कैसे है फायदेमंद

मेथी, अलसी के बीज और काले तिल से तैयार ये पाउडर पीरियड्स संबंधित कई समस्या को दूर करता है. पेट में दर्द, ऐंठन, क्रैम्प, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, स्ट्रेस, रेगुलर पीरियड्स साइकिल, अच्छी नींद लेने में बेहद कारगर है. काली तिल पीरियड्स को रेगुलर बनाने के साथ ही पीरियड्स के दर्द को भी दूर करता है. मेथी के बीज फाइटोएस्ट्रोजेन्स से भरपूर होते हैं, जिसका एस्ट्रोजेन लेवल पर पॉजिटिव एफेक्ट पड़ता है. ये पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो को सुधारता है. साथ ही इसके सेवन से वजन कम होता है, शुगल लेवल भी बढ़ने नहीं देता है.

'फंगल संक्रमण' के कारण क्या हैं?

फंगल इंफेक्शन से पीड़ित लोगों की संख्या भी कम नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला यह फंगल संक्रमण आपको एक समय के बाद पूरी तरह सदमे में डाल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? किस बात का ध्यान रखा जा सकता है? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं...

कारण क्या हैं?:

गर्म और आर्द्र वातावरण इस समस्या का कारण बनता है।

जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है उनमें फंगल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है।

गीले कपड़े पहनना।

तंग जूते या कपड़े पहनना।

लंबे समय तक मोज़े पहने रहना।

व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान न रखना।

एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव

कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली

1. कैंडिडा अल्बिकन्स : यह एक फंगल संक्रमण है जो जननांगों के पास मुंह के पास की त्वचा, नम त्वचा पर होता है।

2. दाद : यह भी एक फंगल संक्रमण है। जो मुख्य रूप से त्वचा, खोपड़ी, पैरों, जांघों और जननांगों के पास होता है।

किस बात का ध्यान रखें?:

व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।

बाथरूम या सार्वजनिक स्नान क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें।

हर समय एक जैसे मोज़े न पहनें।

ज्यादा टाइट जूते न पहनें।

किसी का सामान प्रयोग न करें।

प्रभावित क्षेत्र पर दिन में 3-4 बार 2.5 PH के अम्लीय पानी का छिड़काव करना चाहिए।

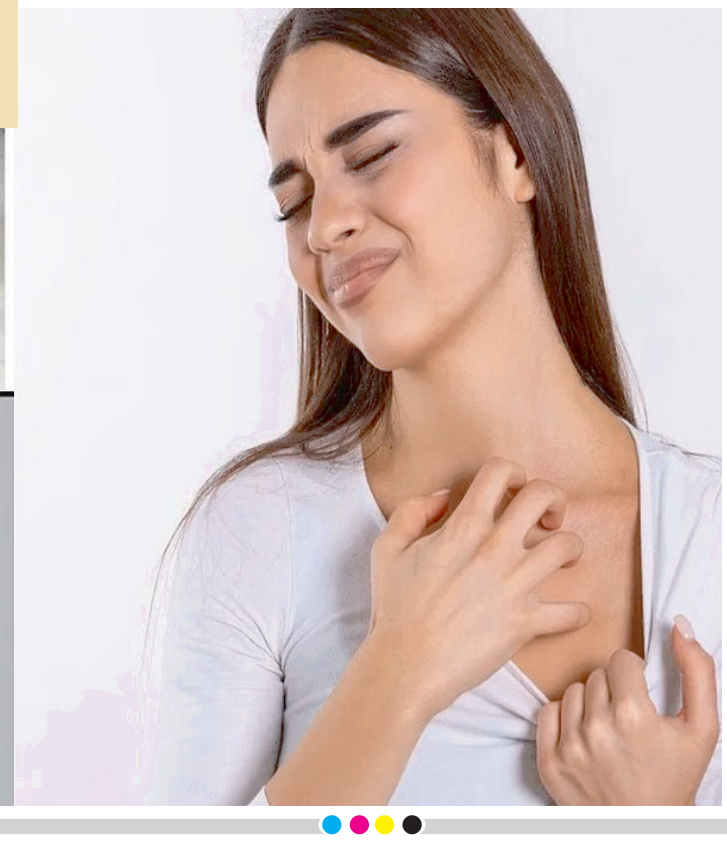

ज्योतिषी- ग्रह- नक्षत्र
चंद्रमा ग्रह - मोती रत्न

रत्न शास्त्र में सभी 9 ग्रहों के लिए अलग-अलग रत्न बताए गए हैं। हर रत्न का जीवन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए और इसके शुभ प्रभाव के लिए ₹मोती₹ धारण करने की सलाह दी जाती है।

यदि रत्न उचित समय पर व पूरे शास्त्र सम्मत तरीके से पहना जाए तो निश्चित उसका बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है।

चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, यदि यह कुंडली में अच्छी अवस्था में होगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा और जब वह व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा तो उसके संकल्प भी सिद्ध होंगे।

आइये जानते हैं मोती धारण करने की विधि और फायदे-:

किस धातु में पहने मोती-:

शुभ मुहूर्त में मोती अच्छी क्वालिटी का ₹चांदी₹ की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए।

इस दिन धारण करना चाहिए मोती-:

मोती धारण करने के लिए सबसे उत्तम दिन शुक्ल पक्ष का सोमवार माना गया है। जबकि इसे धारण करने के लिए ₹अनामिका उंगली₹ और शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए।।

मोती के साथ ना पहने ये रत्न-:

मोती के साथ हीरा, नीलम, ओपल, पन्ना और गोमेद नहीं पहनना चाहिए। मोती के साथ पुखराज धारण करना सर्वोत्तम होता है।।

मोती किसके लिए है अच्छा-:

हमेशा विशेषज्ञ को कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करना चाहिए और वैसे मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के जातकों को मोती धारण करना अच्छा होता है।

अच्छे भाव में चंद्रमा है तो मोती जरूर पहनें-:

यदि आपकी जन्म कुंडली मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न की है और चंद्रमा आपके शुभ भावों में विराजमान हैं जैसे- 1/4/5/9/10/ 11 भाव में है तो आपको मोती काफी सुख, शान्ति, समृद्धि, लाभ प्रदान करने वाला होगा।

किसे नहीं धारण करना चाहिए मोती-:

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मिथुन, कन्या, मकर, तुला, धनु और कुंभ लग्न के जातकों को मोती धारण करना नुकसानदेह साबित हो सकता है।।

मोती पहनने से पहले कुछ सावधानियां अनिवार्य-:

रत्न धारण करने से पहले यह देख लें कि कहीं 4, 9 और 14 तिथि तो नहीं है. इन तिथि को रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि जिस दिन रत्न धारण करें उस दिन गोचर का चंद्रमा आपकी राशि से 4,8,12 में ना हो। अमावस्या, ग्रहण और संक्रान्ति के दिन भी रत्न धारण ना करें।

पूर्ण अवलोकन के बाद ही रत्न धारण करें-:

रत्न धारण करने से पहले लग्न चार्ट/चंद्र कुंडली/ और नवमांश कुंडली चार्ट जरूर देखें। तदोपरांत ही रत्न धारण करने की सलाह दें।।

दिल्लीवालों के लिए अच्छा गया यह वर्ष

CAQM ने वायु गुणवत्ता को लेकर दी अच्छी खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष 200 दिन अच्छी से मध्यम की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। अगर कोविड महामारी के दौरान का वर्ष 2020 को छोड़ दें तो यह 2015 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिनों तक दिल्ली में वायु की गुणवत्ता ऐसी रही हो।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष 200 दिन ₹अच्छी से मध्यम₹ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। अगर कोविड महामारी के दौरान का वर्ष 2020 को छोड़ दें तो यह 2015 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिनों तक दिल्ली में वायु की गुणवत्ता ऐसी रही हो।

वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लागने की वजह से दिल्ली की हवा साफ हो गई थी। अब 2015 के बाद से पहली बार हुआ है कि दिल्ली में 200 दिन हवा साफ रही है।

किस वर्ष कितने दिनों तक साफ रही हवा

दिल्ली में सोमवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi AQI) 175 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। सीएक्यूएम ने बताया कि 2015 के बाद पहली बार (कोविड प्रभावित वर्ष 2020 को छोड़कर) दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 दिनों के लिए 'अच्छे से मध्यम' एक्यूआई श्रेणी में रहा है।

आयोग ने बताया कि वर्ष 2019 में 174 दिन, 2021 में 183 दिन और 2022 में 154 दिन वायु की गुणवत्ता अच्छी से मध्यम रही थी।

AQI से वायु प्रदूषण का चलता है पता

वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) एक नंबर होता है, जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को आंका जाता है। इससे वायु में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाया जाता है। एक्यूआई की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब, और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है।

एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम को जारी किया नोटिस

पार्क में लगाए मोबाइल टावर को लेकर देना होगा जवाब

सरिता विहार के पॉकेट-ए स्थित पार्क में लगाए गए मोबाइल टावर के विरुद्ध जन कल्याण समिति द्वारा भेजी भेजी गई लेटर-पिटीशन का संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से आठ सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह भी कहा कि जिस मोबाइल कंपनी ने टावर लगाया है उसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया जाए।

नई दिल्ली। सरिता विहार के पॉकेट-ए स्थित पार्क में लगाए गए मोबाइल टावर के विरुद्ध जन कल्याण समिति द्वारा भेजी भेजी गई लेटर-पिटीशन का संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से रिपोर्ट मांगी है।

एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आवेदन में उठाए गए मुद्दा अहम है। एनजीटी ने एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि जिस मोबाइल कंपनी ने टावर लगाया है उसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया जाए।

स्वास्थ्य के लिए खतरा है टावर: शिकायतकर्ता

आवेदनकर्ता जन कल्याण समिति ने पत्र में कहा कि पार्क में लगाया गया मोबाइल टावर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह भी कहा कि पार्क में टावर लगाए जाने के कारण बच्चे पार्क में खेलने से वंचित हो गए हैं।

वहीं, स्थानीय नागरिक व वरिष्ठ नागरिक भी व्यायाम समेत अन्य विभिन्न कार्यों के लिए पार्क का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

मदन लाल खुराना मेमोरियल लीग का आयोजन किया गया

डॉ हर्षवर्धन ने खुराना साहब की कप्तानी में खेले गये क्रिकेट मैच को याद करते हुए कहा कि ये क्रिकेट मैच उन्हें याद करने का एक अच्छा जरिया है। सांसद मनोज तिवारी ने स्वर्गीय मदन लाल खुराना को विजनरी लीडर बताया। कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट शिवम छाबड़ा और संयम छाबड़ा ने सबका आभार जताया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।

नई दिल्ली। पीतमपुरा के गेला राम पार्क में तीसरे श्री मदन लाल खुराना मेमोरियल कमल क्रिकेट लीग का फाइनल मैच हुआ। फाइनल मुकाबले में आकाश इलेवन की टीम ने योगी इलेवन को हराकर कप पर कब्ज़ा किया। योगी इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए योगी इलेवन केवल 76 रन ही बना सकी। आकाश इलेवन ने इस लक्ष्य को 21 बॉल शेष रहते 11 ओवर 3 बॉल में ही हासिल कर योगी इलेवन पर 5 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की।

फाइनल मैच में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद डॉ हर्षवर्धन मुख्य अतिथि रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी और बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉ संजय मयूख, बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष राकेश तिवारी,जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, जाने माने हास्य कलाकार दीपक सैनी, निगम पार्षद रेखा गुप्ता, अमित नागपाल, बीजेपी नेता संजीव शर्मा, नीलकान्त बक्शी ने मैच का आनंद लिया साथ ही खुराना जी को श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर डॉ हर्षवर्धन ने खुराना साहब की कप्तानी में खेले गये क्रिकेट मैच को याद करते हुए कहा कि ये क्रिकेट मैच उन्हें याद करने का एक अच्छा जरिया है। मनोज तिवारी ने स्वर्गीय मदन लाल खुराना को विजनरी लीडर बताया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ हर्षवर्धन ने विनर और रनर अप टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही मैन ऑफ दी मैच अभिषेक ठाकरान और पूरी सीरीज़ में बेहतरीन गेंदबाज़ी के लिए मैन ऑफ दी सीरीज़ निखिल को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट शिवम छाबड़ा और संयम छाबड़ा ने सबका आभार जताया।

सीएम केजरीवाल ने दिव्यांगजनों को राज्य पुरस्कार से किया सम्मानित, बोले- 'मैं इन लोगों से सीख कर जा रहा हूं...'

सीएम केजीरवाल ने दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए समारोह में कहा कि दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार बहुत कुछ कर रही है और आगे भी इनके लिए काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया है कि जो दिव्यांग होने के बाद भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाह ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में दिव्यांगजनों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हर किसी की है अपनी एक कहानी

सीएम केजीरवाल ने दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए समारोह में कहा कि दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार बहुत कुछ कर रही है और आगे भी इनके लिए काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया है कि जो दिव्यांग होने के बाद भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, कोई कुछ और है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है।

यह देखें वीडियो

केजरीवाल ने आगे कहा कि इन लोगों की कहानियों को अखबारों में विज्ञापन देकर छापा जाना चाहिए, इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये लोग बहुत से लोगों को बल दे सकेंगे। मैं स्वयं इन लोगों से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूं। इन लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है अगर कोई भी योजनाएं बनानी की जरूरत पड़ी तो उन्हें बनाया जाएगा। इन लोगों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।

घर के बाहर बैठे हिस्ट्रीशीटर को बदमाशों ने मारी गोली, ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर ईंट से कुचला मुंह

अशोक विहार के जेलर वाला बाग इलाके में घर के बाहर बैठे हिस्ट्रीशीटर पर बदमाशों ने गोली चला दी। जब वह भागने लगे तो एक बदमाश फिसलकर गिर गया और आसपास के लोगों ने पकड़कर उसके सिर पर ईंट व पत्थरों से वार कर उसे अधमरा कर दिया। हिस्ट्रीशीटर की पहचान इलाके के रविकांत उर्फ डब्ल्यू के रूप में हुई है। आसपास के लोग उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गए हैं।

दिल्ली। अशोक विहार के जेलर वाला बाग इलाके में घर के बाहर बैठे हिस्ट्रीशीटर पर बदमाशों ने गोली चला दी। जब वह भागने लगे तो एक बदमाश फिसलकर गिर गया और आसपास के लोगों ने पकड़कर उसके सिर पर ईंट व पत्थरों से वार कर उसे अधमरा कर दिया। हिस्ट्रीशीटर की पहचान इलाके के रविकांत उर्फ डब्ल्यू के रूप में हुई है। आसपास के लोग उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गए हैं। खबर लिखे जाने तक बदमाश घायल अवस्था में सड़क पर ही पड़ा था और उसके दो साथी रेलवे लाइन की तरफ भाग गए थे।

सट्टा चलाता है हिस्ट्रीशीटर

सूत्रों के अनुसार, रविकांत उर्फ डब्ल्यू हिस्ट्रीशीटर है और जेलर वाला बाग इलाके में सट्टा चलाता है। सोमवार रात करीब आठ बजे तीन बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और डब्ल्यू पर गोली चलानी शुरू कर दी।

छाती में लगी गोली

इस दौरान दो गोली डब्ल्यू की छाती में लगी और वह गिर गया। आसपास के लोग डब्ल्यू को अस्पताल लेकर गए। डब्ल्यू को गोली मारकर भाग रहे आरोपितों में से एक रघू फिसलकर सड़क पर गिर गया।

पकड़े गए बदमाश का सिर ईंट से कुचला

गुस्साए लोगों ने ईंट-पत्थरों से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। खबर लिखे जाने तक वह सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। रघू भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी। इस बारे में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है।

आईआरसीटीसी स्कैम मामले में दिल्ली की अदालत पहुंचे तेजस्वी यादव, विदेश जाने की मांगी अनुमति

रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले (IRCTC Scam) में सुनवाई के दौरान आरोपित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राउज एवेन्यू कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति देने और पासपोर्ट जारी करने को लेकर आवेदन दायर किया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आवेदन का संज्ञान लेने के बाद मामले को 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

नई दिल्ली। रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले (IRCTC Scam) में सुनवाई के दौरान आरोपित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राउज एवेन्यू कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति देने और पासपोर्ट जारी करने को लेकर आवेदन दायर किया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आवेदन का संज्ञान लेने के बाद मामले को 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने तेजस्वी के अधिवक्ता को आवेदन की कॉपी सीबीआई को देने को कहा। वहीं, सुनवाई के दौरान सह-आरोपित सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता की तरफ से दलील रखी गई। अब मामले में तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी की तरफ से आगे की सुनवाई में दलील रखी जाएगी। अदालत ने मामले को 20 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

सीबीआई ने आरोपपत्र में क्या कहा?

अदालत सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। सीबीआई ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू भारत के रेल मंत्री रहे, उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में केटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इसी दौरान झारखंड के रांची और उड़ीसा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई।

मयूर विहार में डॉक्टर ने अपार्टमेंट की पहली मंजिल से कूदकर किया सुसाइड, काफी दिनों से थे अवसाद में

दिल्ली के मयूर विहार स्थित शिखर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से कूदकर एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने डॉक्टर के शव को कब्जे में ले लिया है और विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मयूर विहार स्थित एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल से कूदकर जीबी पंत के एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली।

नई दिल्ली। दिल्ली के मयूर विहार स्थित शिखर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से कूदकर एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने डॉक्टर के शव को कब्जे में ले लिया है और विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मयूर विहार स्थित एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल से कूदकर जीबी पंत के एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से जान गंवाने वाले डॉक्टर अवसाद में चल रहे थे।

सात क्षेत्रों में प्रदूषण पर वार कर जहरीली हवा को किया जाएगा शुद्ध, लोगों को मिलेगी राहत

गाजियाबाद में सात क्षेत्रों में प्रदूषण पर वार कर जहरीली हवा को शुद्ध किया जाएगा। हवा को खराब होने से रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिक धूल व धुआं उड़ने वाले क्षेत्रों की सूची तैयार की है। इसमें साहिबाबाद राजनगर एक्सटेंशन लोनी भोपुरा दिल्ली बोर्डर जीटी रोड साउथ साइड संजय नगर व सिद्धार्थ विहार शामिल हैं।

साहिबाबाद। प्रदूषण बढ़ने से जिले की हवा लगातार जहरीली हो रही है। इससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। इसकी रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले में अधिक प्रदूषण वाले सात हॉट स्पॉट चिह्नित किए हैं। अब इन क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को रोक कर जहरीली हवा को शुद्ध किया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि इससे लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। जिले की हवा को खराब होने से रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिक धूल व धुआं उड़ने वाले क्षेत्रों की सूची तैयार की है। इसमें साहिबाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, लोनी, भोपुरा दिल्ली बोर्डर, जीटी रोड साउथ साइड, संजय नगर व सिद्धार्थ विहार शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विकास मिश्र का कहना है कि प्रदूषण रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। हाटस्पाट क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाएगी।

सभी क्षेत्रों के लिए टीम गठित की गई हैं। टीम के अधिकारी मौके पर पहुंच कर प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। संबंधित विभागों को भी धूल व धुआं फैलने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

हॉट स्पॉट में प्रदूषण फैलने के ये हैं मुख्य कारक

साहिबाबाद: औद्योगिक उत्सर्जन, अधिक यातायात, सड़क की धूल, आग की घटना, निर्माण गतिविधियां आदि।

राजनगर एक्सटेंशन : निर्माण कार्य, सड़कों पर उड़ रही धूल, कूड़ा जलाने की घटना।

लोनी : खुले में पड़ी निर्माण सामग्री, निर्माण कार्य, कच्ची सड़कें, औद्योगिक उत्सर्जन, दिल्ली-सहारनपुर रोड पर निर्माण गतिविधि।

भोपुरा-दिल्ली बार्डर : खुले में निर्माण सामग्री का भंडारण, सड़कों पर उड़ती धूल, अपशिष्ट जलाना।

जीटी रोड साउथ साइट : औद्योगिक उत्सर्जन।

संजय नगर : अधिक यातायात, सीएनजी व ईंधन रिफिल स्टेशनों पर यातायात।

सिद्धार्थ विहार : निर्माण गतिविधियां, सड़कों पर उड़ती धूल।

पिछले साल के मुकाबले घट गए हॉट स्पॉट

जिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हॉट स्पॉट चिह्नित किए हैं। बीते साल जिले में करीब 30 हाटस्पाट चिह्नित किए गए थे। इस साल केवल सात किए गए हैं। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि विकास कार्य होने से पिछले साल के सापेक्ष इस बार सुधार हुआ है।

इस साल अभी तक 60 दिन खराब खराब श्रेणी में रही जिले की हवा

गुणवत्ता	दिन
मध्यम (101-200)	127
खराब (201-300)	60
बेहद खराब (301-400)	19
गंभीर (401 से अधिक)	02

जिले में हाटस्पाट चिह्नित कर लिए गए हैं। सभी विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करनी होगी। जिस विभाग के इलाकों में आग जलने से धुआं व निर्माण गतिविधियों से धूल उड़ने की घटना होगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

-विकास मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी

भूमि विवादों का वरासत अभियान से होगा समाधान, जमीन को लेकर होने वाली आपराधिक घटनाओं पर लगेगी रोक

भूमि विवादों के लिए होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए वरासत अभियान आरंभ किया गया है जो 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। अपने व परायों के बीच भूमि विवाद का समय पर निस्तारण नहीं होने के कारण कई बार यह खूनी विवाद में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इसी वजह से यह अभियान शुरू किया गया है।

गाजियाबाद। भूमि विवादों के लिए होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए वरासत अभियान आरंभ किया गया है, जो 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। अपने व परायों के बीच भूमि विवाद का समय पर निस्तारण नहीं होने के कारण कई बार यह खूनी विवाद में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इसी वजह से यह अभियान शुरू किया गया है। जिले की सदर, मोदीनगर और लोनी तहसील स्तर पर बड़ी संख्या में भूमि विवादों के मामले लंबित चले आ रहे हैं। इनमें सीमांकन, निर्विवाद वरासत, नामांतरण और बंटवारे के लंबित मामले शामिल हैं। लंबित मामलों के चलते भूमि विवाद में आपसी झगड़े होते हैं जो बड़ी घटनाओं का रूप ले लेते हैं। कई मामलों में लोग एक-दूसरे की जान तक ले चुके हैं। वरासत अभियान के तहत संबंधित लंबित सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। वरासत अभियान के दौरान संबंधित लंबित सभी मामलों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समयावधि में कारण विशेष से किसी प्रकरण का निस्तारण न होने पर इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

इस संबंध में जिलाधिकारी, राकेश कुमार सिंह ने कहा-

तहसील दिवस में भूमि विवादों को लेकर काफी शिकायतें मिल रही हैं। कई बार भूमि विवाद बड़ी घटनाओं का भी रूप ले रही हैं। शासन की मंशा के अनुरूप इन विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया गया है।

जमीनी विवाद में रिश्ते भी तार-तार

सात अक्टूबर 2023: विजय नगर में भूमि विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी।

दो अक्टूबर 2023: मुरादनगर के गांव मकरेड़ा में रिश्ते के भाई ने जमीनी विवाद के चलते भाई को बुलाकर गोली मार दी।

आठ जनवरी 2023: लोनी के खानपुर गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए

लंबित मामले निस्तारित न होने पर अफसरों की जवाबदेही होगी तय, भूमि विवाद में खूनी घटनाएं रोकने को पहल

लेखपालों की स्थिति

तहसील	तैनात	पद
मोदीनगर	29	43
सदर	18	24
लोनी	12	16
कुल	59	83

नोट: कुछ लेखपालों को कार्यालयों में भी अटैच किया गया है।

लेखपला संघ के जिलाध्यक्ष, सुधीर शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन सरकारी योजनाओं को पूरा करने की समयसीमा निर्धारित है। लेखपाल इन योजनाओं के अलावा राजस्व के अन्य कार्य भी कर रहे हैं। एक-एक लेखपाल के पास 14 से 15 गांव का कार्य है। खसरा, रियल टाइम खतौनी का पोर्टल काफी धीमा है। रात-रात भर इंतजार कर कार्य को समयावधि में पूरा करते हैं। वर्ष 2016 से लेखपालों की भर्ती नहीं हुई।

फर्जीवाड़ा कर आरोपित ने शख्स को लगाई 15 लाख की चपत, खाते से दस्तावेज निकाल कर लिया 2 बार लोन

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वैभव खंड के युवक से 15 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन ले लिया और क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पार्श्वनाथ मजेस्टिक सोसायटी के रतनदीप सिंह बताया कि उनके खाते से फर्जी दस्तावेज लगाकर दो लोन ले लिए गए। इतना ही नहीं फर्जी दस्तावेज से एक क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिया गया।

साहिबाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वैभव खंड के युवक से 15 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन ले लिया और क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। पीड़ित ने इंदिरापुरम कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पार्श्वनाथ मजेस्टिक सोसायटी के रतनदीप सिंह बताया कि उनके खाते से फर्जी दस्तावेज लगाकर दो लोन ले लिए गए। इतना ही नहीं फर्जी दस्तावेज से एक क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिया गया, जिससे उन्हें 15 लाख की चपत लगाई गई। उन्होंने ऑनलाइन लोगिन कर खाते की डिटेल देखी तो फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। मई 2023 में लोन और क्रेडिट कार्ड बनाया गया।

उन्होंने बताया कि दस्तावेज में लगाई गई ईमेल आईडी, पता और मोबाइल नंबर सब फर्जी है। पता दिल्ली के उत्तम नगर का दिया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साइबर सेल की मदद से जांच कराई जा रही है।

मेरे दिमाग में शैतान घुस गया था..बहुत गलत किया', दरिंदगी के बाद भांजी को मारने वाले आरोपी ने कुबूल किया गुनाह

भांजी से अश्लीलता कर मुंह दबाकर हत्या करने के आरोपित चचेरे मामा ने सिपाही की सर्विस पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपित के बायें पैर में गोली लग गई जिसके बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर नगर कोतवाली पुलिस ने जिला एमएमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया।

गाजियाबाद। मेरे दिमाग में शैतान घुस गया था। कुछ समझ नहीं आया, क्या गलत क्या सही। तब समझ नहीं आया कि क्या कर रहा हूं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। सात साल की भांजी से अश्लील हरकत कर हत्या करने के आरोपित ने पुलिस के सामने अपने अपराध को कुछ यूं बयान किया और फिर कुछ नहीं बोला।

इस घिनौने कृत्य की शुरुआत आरोपित के पोर्न वीडियो देखने से हुई, जैसा कि पुलिस की छानबीन में सामने आया है। उसका मोबाइल को खंगाला तो उसमें कई अश्लील वीडियो मिले। इनसे पता चलता है कि आरोपित अश्लील वीडियो देखता था।

प्रलोभन देकर बच्ची को कमरे में ले गया था आरोपी

पता चला है कि घटना को अंजाम देने से पहले वह अपने घर में अकेले यही वीडियो देख रहा था। इसके बाद वह बच्ची के पास गया और उसे मामा के घर से बुलाकर काजू-बादाम खिलाने का प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया।

रिश्तों को भुलाकर खुद को मामा बुलाने वाली मासूम से न सिर्फ गलत काम किया बल्कि मुंह दबाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया ताकि उसकी इस शर्मनाक हरकत के बारे में दूसरों को न पता चले। मगर अपने मंसूबों में वह कामयाब नहीं हो पाया। बच्ची का शव उसकी नापाक हरकत की गवाही साफ दे रहा था।

बच्चों को कैसे बचाएं?

बच्चों से होने वाली ऐसी अधिकांश घटनाओं में करीबी ही सामने आता है। चाहे वह पड़ोसी हो, शिक्षक हो, रिश्तेदार, माता-पिता का दोस्त या पड़ोसी। जिला एमएमजी अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. अनिल कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि बच्चों को रिश्तेदारी में जाने से तो नहीं रोक सकते।

तेजी से बदलते समाज में बच्चों को यौन शोषण से बचाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसीलिए बच्चों को सही गलत के बारे में ढंग से बताना जरूरी हो गया है। शिक्षा नीति में भी यह प्रविधान किया जा रहा है कि उन्हें गुड व बैड टच की पहचान करना सिखाएं। माता-पिता उनकी बात सही तरीके से सुनें और वे क्या बता रहे हैं, इसको लेकर भी स्पष्ट रहें। यह एक भावनात्मक हादसा होता है, जो शारीरिक हादसे से कहीं अधिक खतरनाक होता है। शारीरिक हादसे से दवाइयां उबार लेती हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति का सामना करके निकले बच्चे को तुरंत समझाने न लगें।

वो कौन-से कारण हैं जिसके चलते देश में जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं है भाजपा?

नीरज कुमार दुबे

जहां तक भाजपा के इस पर आधिकारिक रुख की बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन आयेगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी।

देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता अपनी रैलियों, सभाओं, संवाददाता सम्मेलनों और सोशल मीडिया पोस्टों के जरिये केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना करवाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है और सबसे बड़ी आबादी भी गरीब की ही है तथा उनकी सरकार अपनी हर नीति के केंद्र में इस वर्ग को रखती है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। जहां तक जातिगत गणना के मुद्दे पर मोदी सरकार के आधिकारिक रुख की बात है तो वह अदालत में तभी स्पष्ट हो गया था जब सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि जनगणना करते समय अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं की जाएगी।

दरअसल उस समय तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह जनगणना में पिछड़ी जातियों की भी गणना करे। महाराष्ट्र की तत्कालीन शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना में तत्कालीन सरकार ने एक आयाम जोड़ा था, जिसके अंतर्गत जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। सरकार ने वे आंकड़े उस वक्त जाहिर नहीं किए थे लेकिन उन्हें अब जारी किया जाना चाहिए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के उस तर्क का विरोध करते हुए मोदी सरकार ने अदालत से कहा था कि उस समय इकट्ठे किए गए आंकड़े इतने अजीबो-गरीब थे कि उन्हें जाहिर करना उचित नहीं होगा।

जहां तक भाजपा के इस पर आधिकारिक रुख की बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन आयेगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी। वैसे यहां सवाल उठता है कि भाजपा आखिर क्यों नहीं चाहती कि जाति के आधार पर जनगणना हो? जबकि देखा जाये तो अन्य कारणों के अलावा, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा की प्रचंड जीत अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के मतदाताओं के बीच बनाई गई महत्वपूर्ण पैठ के कारण ही संभव हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा को अन्य जातियों या समुदायों से समर्थन नहीं मिला था। भाजपा अपने पारंपरिक समर्थकों, उच्च जातियों और उच्च वर्गों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के अलावा बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों के मतों को जुटाने में भी कामयाब रही थी। इसलिए यह सवाल उठता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति-आधारित जनगणना कराने के बारे में अनिच्छुक क्यों लगती है?

जरा हालिया राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो बहुत कुछ समझ आ जायेगा। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इस फैसले ने भारत में चुनावी राजनीति की प्रकृति को बदल कर रख दिया था, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में इसका बड़ा असर हुआ था। मंडल के बाद की राजनीति के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और वह मजबूत होकर राज्यों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके मजबूत उदाहरण हैं।

हम आपको बता दें कि 90 के दशक की शुरुआत में भाजपा को अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते ₹कमंडल राजनीति₹ के नाम से जाना जाता था। उस समय कमंडल को मंडल राजनीति का मुकाबला करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा तमाम नेताओं के नेतृत्व में कड़ी मेहनत की और दो सांसदों वाली यह पार्टी केंद्र की सत्ता तक पहुँचने में तभी सफल रही जब उसे पिछड़ों और अति पिछड़ों का भरपूर समर्थन मिला। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणाम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

उस समय भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कर केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई और अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे रखकर एनडीए के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि उस समय भले भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी लेकिन दोनों चुनावों में सर्वाधिक लाभ में क्षेत्रीय दल ही रहे थे। क्षेत्रीय दलों को 1998 में 35.5% और 1999 में 33.9% वोट मिले थे। यहां तक कि जब 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई, तब भी क्षेत्रीय दलों को कुल मिलाकर 39.3% वोट मिले। क्षेत्रीय दलों को 2004 के लोकसभा चुनावों में 39.3% और 2009 के लोकसभा चुनावों में 37.3% वोट मिले थे। यहां तक कि जब भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान 31% वोटों के साथ बहुमत हासिल किया, तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर 39% वोट हासिल किए थे।

इसके अलावा, एक बड़ा आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई थी, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में ही सेंध लग गई थी जिससे उनका वोट शेयर घटकर 26.4% रह गया था। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा ने पिछले एक दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनावों में 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि 42% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया। लेकिन एक दशक के भीतर खासकर ओबीसी नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में उभार के बाद इस समुदाय का समर्थन भाजपा के साथ जुड़ गया जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 27% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया था।

लेकिन ओबीसी वर्ग के भाजपा को प्रचंड समर्थन के बावजूद मामले में एक पेंच है। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान तो ओबीसी मतदाताओं को भाजपा पसंद आती है लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की हो तो उनकी पसंद बदल भी जाती है। आंकड़ों के जरिये समझाने के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में केवल 11% ओबीसी ने राजद को वोट दिया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने राजद को वोट दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 14% ओबीसी ने ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था।

बहरहाल, जहां तक भाजपा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना से बचने की बात है तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी लगता है कि इस कवायद के चलते विभिन्न जातियों, विशेषकर ओबीसी जातियों के बारे में जो आंकड़े सामने आएंगे उससे क्षेत्रीय दलों को भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नये मुद्दे मिल जाएंगे। यदि आंकड़े ऐसे आये कि केंद्र सरकार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटा को नया स्वरूप देना पड़ा तो इसके परिणामस्वरूप मंडल-2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे क्षेत्रीय दलों को नया जीवनदान मिल जायेगा। इसके अलावा कई दल ऐसे भी हैं जो भाजपा को राज्यों और केंद्र में चुनौती देने के लिए तमाम प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन यदि जातिगत आंकड़े सामने आ गये तो वह भाजपा को आसानी से घेर सकते हैं। भाजपा के पास इस समय ओबीसी के सबसे ज्यादा विधायक और सांसद भले हों लेकिन पार्टी कतई नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना करवा कर ऐसे मुद्दे को हवा दी जाये जिसको संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आज का भाजपा नेतृत्व 90 के दशक की मंडल-कमंडल राजनीति से भलीभांति वाकिफ भी है। वह जानता है कि अटल-आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या-क्या प्रयास करने पड़े थे और कैसे-कैसे दिन देखने पड़े थे इसलिए अब जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए राजनीति की जा रही है।

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लगेंगे पंख, इस राज्य में मिला EV बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का बड़ा खजाना

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इससे इलेक्ट्रिक बैटरियां सस्ती होंगी और अंततः इलेक्ट्रिक कारों की कीमत भी कम हो सकेंगी। भारत सरकार ने 2030 तक ईवी को 30 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में लिथियम सबसे आवश्यक धातु है।

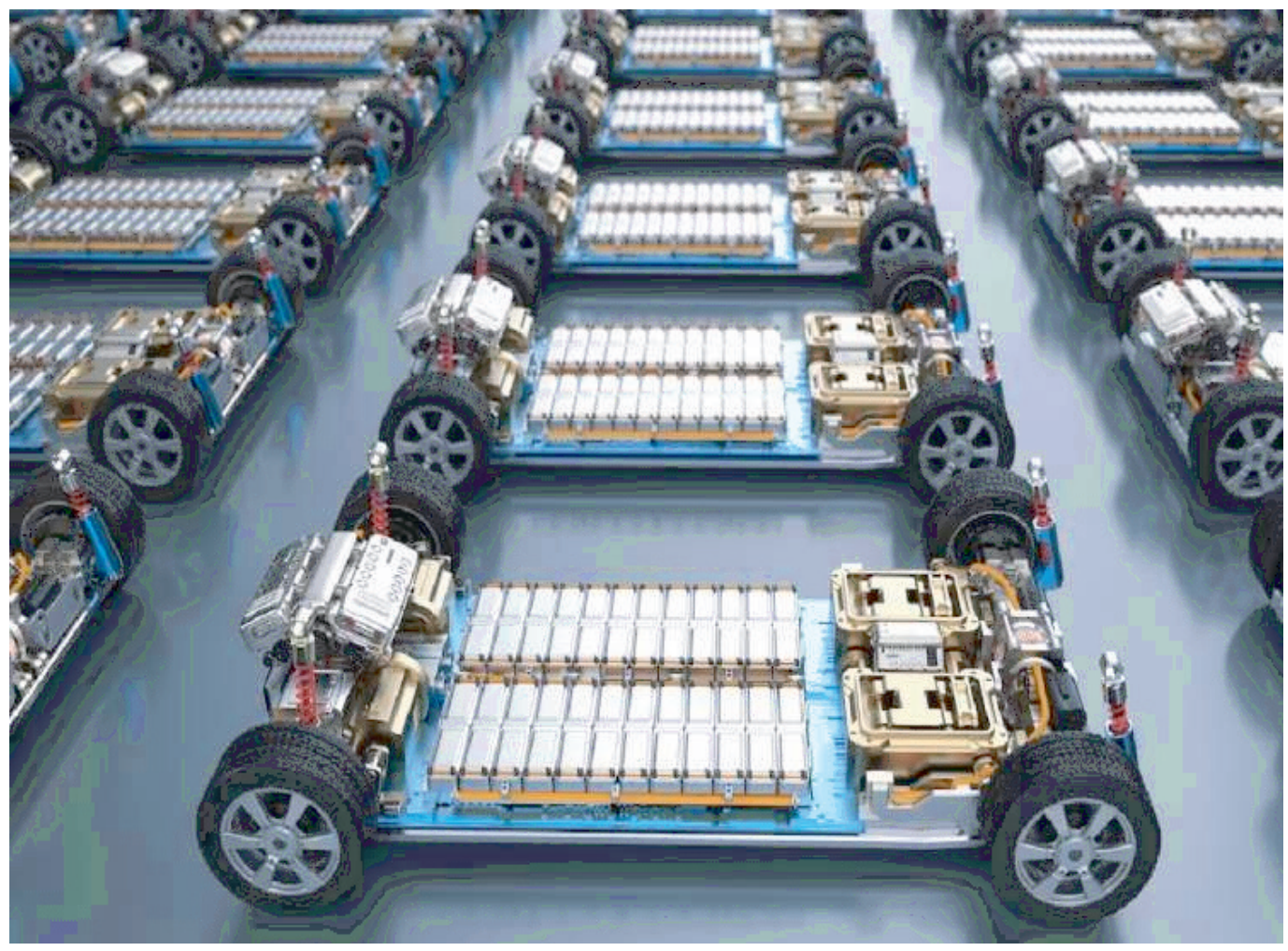

झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह की धरती से निकलने वाले अभ्रक की चमक कभी पूरी दुनिया तक पहुंचती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में न तो अभ्रक की डिमांड रही और न ही उसकी खदानें बचीं। लेकिन इसी धरती के भीतर खोजे गए बेशकीमती खनिज लिथियम के बड़े भंडार ने देश में बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अपार संभावनाएं जगाई हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) ने भू-तात्विक सर्वेक्षण में पाया है कि कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम के अलावा कई दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। पूरी दुनिया में आने वाले वर्षों में जीरो कार्बन ग्रीन एनर्जी के जिन लक्ष्यों पर काम चल रहा है, उसमें लिथियम को गेमचेंजर मिनरल के तौर पर देखा जा रहा है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, सौर पैनल, पवन टरबाइन और अन्य रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में किया जाता है।

कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बाद अब झारखंड तीसरा राज्य

जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल में कर्नाटक में 1600 टन और इसके बाद जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार खोजा था। अब झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह के अलावा पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में इस बेशकीमती धातु के उत्खनन की संभावनाओं पर काम चल रहा है। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया ब्लॉक और उसके आसपास जियोकेमिकल मैपिंग में यहां उपलब्ध लिथियम, सीज़ियम और अन्य तत्वों में हाई कन्स्ट्रेशन (उच्च सांद्रता) पाया गया है। फिलहाल देश का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग अभी भी अपनी लिथियम आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। अभी हम लिथियम का आयात मुख्य तौर पर चीन से करते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक ईवी को 30 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में लिथियम सबसे आवश्यक धातु है। इसलिए लिथियम के उत्खनन की संभावनाओं पर सरकार का खास तौर पर फोकस है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत होगी कम

ऐसे में कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बाद झारखंड में लिथियम के भंडार की खोज को भविष्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लिथियम का भंडार देश में मिलने से चीन पर निर्भरता खत्म होगी। अभी चीन से भी बैटरी का आयात किया जा रहा है। इससे ईवी की कीमत काफी अधिक है। देश में लिथियम मिलने से बैटरी की कीमत कम होगी। इससे इलेक्ट्रि गाड़ियों के दाम में बड़ी कमी आएगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रि गाड़ियों की कीमत में करीब 40 से 50 फीसदी हिस्सा बैटरी का होता है। बीते जून महीने में पैन एशिया मेटल्स लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और झारखंड में लिथियम खनन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की थी। सीएम ने कहा था कि झारखंड सरकार नियमों के अनुसार लिथियम प्रोडक्शन की संभावनाओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी।

इन जिलों में मिला खदान

जीएसआई के सर्वे के अनुसार झारखंड के कोडरमा के तिलैया ब्लॉक और ढोढ़ाकोला-कुसुमा बेल्ट में लिथियम के अलावा सिजियम, गिरिडीह के गांवा ब्लॉक और कोडरमा के पिहरा बेल्ट में एलआई (ली), सिजियम, आरईई और आरएम जैसे धातुओं का भंडार होने की संभावनाएं हैं। विगत 29 सितंबर को झारखंड सरकार के भूतात्विक पर्षद की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में लिथियम की खोज के परिणामों पर चर्चा की गई। सरकार ने राज्य में लिथियम खनन की संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। निवेशकों ने भी इसे लेकर अपनी रुचि प्रदर्शित की है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इससे इलेक्ट्रिक बैटरियां सस्ती होंगी और अंततः इलेक्ट्रिक कारों की कीमत भी कम हो सकेंगी।

ईवी चार्ज कर रहे हैं तो इन जरूरी टिप्स को अपनाएं, सुरक्षा के साथ बढ़ेगी बैटरी लाइफ भी

दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, इन बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा सावधानियां भी ईवी खरीदारों और मालिकों के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। इंटरनल कंब्शन इंजन (आईसीई) से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों में काफी कम मूविंग पार्टस होते हैं। हालांकि, चुनिंदा परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की संभावना विशेष रूप से होती है। साथ ही, ईवी में लगी आग की तीव्रता आईसीई वाहन में लगी आग की तुलना में बहुत ज्यादा होती है।

ईवी में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वे बिजली से चलते हैं, और बैटरी पैक पावर जेनरेट करते समय अत्यधिक गर्मी भी पैदा करता है। इलेक्ट्रिक वाहन को सुरक्षित वातावरण में चार्ज करना चालक की सुरक्षा और वाहन के बैटरी पैक के स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को कहां चार्ज करते हैं, चाहे वह घर पर हो या सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन पर, कुछ एहतियाती सुझावों का पालन करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां हम आपको कुछ अहम टिप्स बता रहे हैं।

प्रमाणित चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करें

सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या से बचने के लिए हमेशा प्रमाणित चार्जर और प्रमाणित चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करें। प्रमाणित चार्जिंग स्टेशन और उनके चार्जर सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं और ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो कही और चार्ज करने पर आपके ईवी के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं।

अत्यधिक तापमान में चार्ज करने से बचें

अत्यधिक तापमान आपके वाहन के बैटरी पैक के लिए हानिकारक हो सकता है और इसकी वजह से बैटरी की लाइफ भी कम हो सकता है। इसलिए, अत्यधिक तापमान में ईवी को चार्ज करने से बचने की हमेशा सलाह दी जाती है। ईवी को सीधी धूप में चार्ज करने से बचें, क्योंकि गर्मी का असर चार्जिंग सिस्टम और बैटरी पैक पर भी पड़ सकता है।

गीली स्थितियों में चार्ज करने से बचें

पानी के साथ बिजली का कोई मेल नहीं है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा सुरक्षा पर जोखिम होता है। इसलिए, गीली परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ईवी को गीली स्थिति में चार्ज किया जाना है, तो हमेशा सुनिश्चित करें कि चार्जिंग स्टेशन और केबल पानी के संपर्क में न आएं।

ज्यादा चार्ज न करें

ओवरचार्जिंग किसी भी बैटरी के लिए खराब है, चाहे वह स्मार्टफोन की हो या इलेक्ट्रिक वाहन की। ओवरचार्जिंग से बैटरी खराब हो सकती है और उसकी लाइफ काफी कम हो सकता है। ज्यादातर आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए एक बिल्ट-इन मैकेनिज्म (अंतर्निर्मित तंत्र) के साथ आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहन की चार्जिंग प्रक्रिया पर नजर रखना महत्वपूर्ण होता है।

इस माह लॉन्च हो सकती है टाटा पंच इलेक्ट्रिक, सामने आई कीमत

पंच ईवी की शुरुआती कीमत 12 लाख रु हो सकती है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन निर्माता कंपनी, टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच जल्द इलेक्ट्रिक अवतार में आ सकती है। इसके कयास काफी पहले से लगाए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स इस माह एसयूवी पंच के इलेक्ट्रिक वैरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। बता दें कि, टाटा मोटर्स की ओर से पहले पुष्टि की गई थी कि वह इस साल के आखिर तक तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करेगी। हाल ही में कंपनी ने अपनी नेक्सन ईवी के फेस्लिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में उतारा है। इस एसयूवी में कई सारे बेहतरीन फीचर्स और अट्रैक्टिव एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन देखने को मिलती है। **आइए जानते हैं पंच ईवी (Punch EV) से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में...**

पंच ईवी में क्या होगा खास स्पाई तस्वीरों से चता चलता है कि, पंच ईवी हैरियर और सफारी जैसी एसयूवी से प्रेरित होगी। इसमें रीडिजाइन किया गया फ्रंट लुक देखने को मिल सकता है। इसमें वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट सेटअप के साथ-साथ डिजिटल लोगो के साथ टाटा का नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल सकता है। क्या कहती है मीडिया रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि, Punch EV कंपनी की ओर से पेश किए जाने वाला अगला प्रोडक्ट होगा, जिसे अक्टूबर महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि, टाटा मोटर्स लंबे समय से पंच के इलेक्ट्रिक अवतार की टेस्टिंग कर रहा है और कई अलग-अलग मौकों पर इसे स्पॉट भी किया गया है। रिपोर्ट की मानें तो, Punch EV कंपनी के मौजूदा जिप्ट्रॉन पावरट्रेन पर बेस्ड होगी, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों में भी करती है। Tata Punch EV के फ्रंट में चार्जिंग सॉकेट दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फोर-व्हील डिस्क ब्रेक, नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का बड़ा ट्चस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ और दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है। इसके डिजाइन में सेंट्रोल कंसोल देखनेको मिल सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज सेपता चलता है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। यह भी पढ़े -टेस्ला का इस साल भारत से 1.9 अरब डॉलर तक के ऑटोमोबाइल पार्ट्स मंगाने का लक्ष्य है : पीयूष गोयल संभावित कीमत लॉन्च से पहले Punch EV की संभावित कीमत सामने आई है। जिसके अनुसार, इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपए हो सकती है, जो कि इसके एडवेंचर वैरिएंट की होगी। वहीं इसके टॉप वैरिएंट की कीमत 14.60 लाख रुपए तक जा सकती है। हालांकि, इसकी सही कीमतों की जानकारी लॉन्च के साथ ही मिल सकेगी।

चीन को आर्थिक टक्कर देगा भारत

डा. जयंतीलाल भंडारी

दुनिया में अमेरिका के बाद चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे क्रम पर है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें क्रम पर है। वैश्विक रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3.7 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। जबकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार भारत से पांच गुना अधिक है।

कंप्यूटर चिप बनाने वाली अमेरिकन कंपनी माइक्रोन के सहयोग से देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलनी होगी। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफडीआई नीतियों और उदार निवेश व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि दुनिया के विकसित और विकासशील देश आर्थिक डगर पर भारत को अधिक तरजीह दें'

यकीनन इस वर्ष 2023 में जी-20 की अध्यक्षता और जी-20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद जी-20 से प्राप्त नई शक्ति को मुट्ठी में लेकर भारत चीन को आर्थिक टक्कर देने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर क्वाड संगठन के प्रति अपने-अपने देश की न सिर्फ प्रतिबद्धता जताई है, बल्कि सीधे तौर पर चीन को यह संदेश भी दिया है कि क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आर्थिक रूप से एक-दूसरे को और मजबूती देंगे। साथ ही मौजूदा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था की जगह एक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था को मूर्त रूप देंगे। जी-20 के सफल आयोजन के साथ दुनिया में यह बात उभरकर सामने आई है कि 'चीन प्लस वन' रणनीति के तहत भारत दुनिया के सक्षम व भरोसेमंद देश के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वाले देश के रूप में नई भूमिका निभा सकता है। दुनिया का कोई दूसरा देश इस तरह के परिचालन के पैमाने और आकार की पेशकश नहीं कर सकता, जैसा भारत में उपलब्ध है।

इसके अलावा जी-20 में घोषित हुए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कारिडोर (आईएमईसी) के माध्यम से रेल एवं जल मार्ग से भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसरों का ऐसा ढेर लगाया जा सकेगा जिससे चीन की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ जाएगी। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद इस समय अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित समाचार पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेशल रिपोर्टों में यह बात भी एकमत से कही जा रही है कि जी-20 की नई शक्ति से सुसज्जित भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश की भूमिका में उभरकर सामने आया है और चीन को आर्थिक टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसे में जहां भारत एक ओर अधिक रणनीतिक प्रयासों से भारतीय बाजार में चीन के प्रभुत्व को कम कर सकता है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के बाजार में उद्योग-कारोबार, निर्यात और निवेश के अधिक मौकों को मुट्ठियों में ले सकता है। निःसंदेह भारत के द्वारा चीन को आर्थिक टक्कर देने की मजबूत स्थिति के कई कारण उभरकर दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक आर्थिक-वित्तीय संगठनों की नई रिपोर्टों में उभरकर दिखाई दे रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर है और भारत की विकास दर चीन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में भारत को एशिया के सबसे उभरते बाजारों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है। भारत में ढांचागत विकास की तेजी, बढ़ते विदेशी निवेश, बढ़ते शेयर बाजार, मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, मध्यम वर्ग की ऊंची क्रय शक्ति, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, बढ़ते हुए कामकाजी उम्र वाले लोग जैसे विभिन्न कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनियाभर में कल तक जिस भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता था, वह अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा बन गया है।

लंबे समय तक भारत को एक अरब से अधिक भूखे पेट वाले लोगों के राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब भारत एक अरब से अधिक आकांक्षी प्रतिभाओं और दो अरब से अधिक कुशल हाथों और युवाओं के राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया है। कोविड महामारी के दौर में जहां भारत ने 150 से अधिक देशों को कोरोना दवाओं व टीकों की आपूर्ति की, वहीं अब तक वैश्विक मंदी की निराशाओं के बीच भारत सक्षम व भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) वाले देश के रूप में उभरकर दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि चीन की बढ़ती हुई आर्थिक समस्याओं और आपदाओं के बीच भारत के लिए आर्थिक अवसरों का नया दौर आकार ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहा है। चीन-ताइवान के बीच चरम पर पहुंची तनातनी और चीन के द्वारा अपनाई जा रही अमेरिका के विरोध की रणनीति के कारण चीन से वैश्विक फंड मैनेजर्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का मोह भंग होने लगा है। घटती मांग के कारण ये चीन के शेयर बाजार से धन निकालकर भारत सहित अन्य देशों में भेज रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों में फैक्टरियां डालना शुरू किया है। चीन से निकलकर एप्पल, सैमसंग जैसी कई बड़ी कंपनियां भारत में काम शुरू कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशक अगले 10 साल में चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा आशान्वित नहीं हैं। वे भारत में अपना आर्थिक भविष्य देख रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जी-20 से भारत की बढ़ी हुई आर्थिक ताकत के बावजूद भारत के द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था को देखते ही देखते पीछे छोड़ना कठिन व चुनौतीपूर्ण है। जहां अप्रैल 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में तो चीन को पछाड़ चुका है, वहीं विकास के मामले में आज भी भारत बहुत पीछे है।

दुनिया में अमेरिका के बाद चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे क्रम पर है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें क्रम पर है। वैश्विक रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3.7 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। जबकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार भारत से पांच गुना अधिक है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से पांच गुना अधिक है। साथ ही अगस्त 2023 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से चीन के विदेशी मुद्रा भंडार का आकार पांच गुना है। ऐसे में इस समय दुनिया के करोड़ों लोग अर्थविशेषज्ञों से यह पूछ रहे हैं कि भारत आर्थिक वृद्धि को गति देकर चीन की अर्थव्यवस्था को कैसे पीछे छोड़ सकता है? इसके जवाब में अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा संभव है, क्योंकि जहां जी-20 से भारत को दुनिया के विकसित और विकासशील देशों से विकास की अभूतपूर्व संभावनाएं मिली हैं, वहीं अब चीन दुनिया के इतिहास का ऐसा पहला देश बनेगा जो अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। चीन में 2050 तक करीब 70 फीसदी आबादी ऐसी होगी जो काम करने वाले लोगों पर निर्भर होगी। फिलहाल यह 35 फीसदी है। निःसंदेह चीन से आगे निकलने के लिए भारत को कई बातों पर ध्यान देना होगा। भारत के द्वारा कार्यकुशलता के स्तर को बढ़ाने और मानव पूंजी को डिजिटल कौशल युक्त बनाने पर काम करना होगा। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी केवल 24 प्रतिशत है, इसे बढ़ाना होगा।

अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई के माध्यम से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा नौकरियां बढ़ानी होंगी। कंप्यूटर चिप बनाने वाली अमेरिकन कंपनी माइक्रोन के सहयोग से देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलनी होगी। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफडीआई नीतियों-उदार निवेश व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि एक मजबूत लोकतंत्र होने के नाते दुनिया के विकसित और विकासशील देश आर्थिक डगर पर भारत को अधिक तरजीह दें। हम उम्मीद करें कि जी-20 के दौरान क्वाड सहित दुनिया के विभिन्न देशों से भारत को चीन प्लस वन रणनीति के साथ-साथ नए निर्मित होने वाले भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक कारिडोर (आईएमईसी) के अभूतपूर्व लाभ मिलने की जो नई संभावनाएं उभरी हैं, भारत उन्हें मुट्ठी में अवश्य लेगा। ऐसे में यदि हम विभिन्न रणनीतियों के साथ चीन को आर्थिक टक्कर देते हुए 8-9 फीसदी विकास दर के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे तो भारत 2047 में दुनिया का विकसित देश बनने के साथ-साथ चीन को विकास की डगर पर पीछे छोड़ने वाले देश के रूप में भी चमकते हुए दिखाई देगा।

संपादक की कलम से

107 पार भी जाना है

हम आज हांगझाउ, चीन एशियाई खेलों का उपसंहार लिख रहे हैं। चीन और जापान विश्व स्तर पर भी खेलों के 'चैम्पियन देश' हैं। हम उनकी होड़ में नहीं हैं और न ही वह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भारत ने अपनी गरीबी और साधनहीनता के साथ खेल की चुनौतियां देना शुरू किया था। हमने अपने राष्ट्रीय खेल 'हॉकी' का स्वर्णिम युग भी देखा और सुना है। उसका पतन भी दुखद रहा है, लेकिन अब 'एशियाई चैम्पियन' बनकर हॉकी ने पुराने दौर को जिंदा रखने की कोशिश की है, यह एहसास बेहद सुखद है। भारतीय हॉकी आज विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ कर हमने सभी देशों की हॉकी को परास्त किया है। हमारे खिलाडियों की मेहनत, जुनून और उनका हुनर अब भारत को 'ओलंपिक चैम्पियन' भी बनाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्रिकेट की पुरुष-महिला टीमों को स्वर्ण पदक 'बैडमिंटन युगल मुकाबले के चैम्पियन' कबड्डी की दोनों टीमों के गले में 'पीला तमगा' 'कमाल की सटीक तीरंदाजी में 'स्वर्णिम बौछार' हुई। इस खेल में भारत ने रिकॉर्ड 9 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। स्क्वैश में भी भारत 'स्वर्णिम महारथी' बना रहा। हमारे अचूक निशानेबाजों ने 'स्वर्णिम लक्ष्य' भेदे। सिफ्ट कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर नया इतिहास लिखा। रुद्रांक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने भी विश्व कीर्तिमान के साथ भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। हमारे खिलाडियों के हिस्से चांदी खूब बरसी है और कांस्य पदक भी गले में सजे हैं। यकीनन यह भारतीय खेल के पुनरोत्थान और ताकत का दौर है।

एशियाई खेलों में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक समेत 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीत कर शतक को भी पार किया है। खेल के अंतिम दिन शनिवार को भारत ने 6 स्वर्ण सहित 12 पदक जीत कर कीर्तिमान बनाया है। 2018 के जकार्ता एशियाड में भारत ने 16 स्वर्ण समेत कुल 70 पदक जीते थे। इस बार हमने 107 पदक हासिल किए हैं। 'इस बार सौ के पार' का सूत्रवाक्य भी हमारे खिलाडियों ने जीवंत और साकार कर दिया है। एशियाड के 72 सालों में पहली बार भारत ने शतक पार पदक जीते हैं। यह उपलब्धि आकस्मिक नहीं है। यदि बेटों ने 52 पदक (15 स्वर्ण, 19 रजत, 18 कांस्य) जीते हैं, तो बेटियां भी 46 पदकों (9 स्वर्ण, 17 रजत, 20 कांस्य) के साथ पीछे नहीं रही हैं। नौ पदक बेटे-बेटियों ने मिलकर मिश्रित मुकाबलों में भी जीते हैं। हमारे स्वर्णिम खिलाडियों ने विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। शाबाशी इसकी भी देनी चाहिए कि एशियाई खेलों के पदकवीरों की सूची में अब भारत चौथे स्थान पर रहा। यह उपलब्धि भी 37 लंबे सालों के बाद अर्जित की गई है। बैडमिंटन का उल्लेख खासतौर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि सात्विक रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अब विश्व में 'नंबर वन' हो जाएगी। यह अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में भारत के माथे स्वर्ण-ताज सजाया है।

चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया आदि देश एशिया में बैडमिंटन के 'चैम्पियन गढ़' रहे हैं। उनकी चुनौतियों को ध्वस्त करके भारतीय जोड़ी ने हमारी झोली में 'स्वर्ण पदक' डाला है। अब लक्ष्य को हासिल करके रुकना नहीं है। यह 107 का सम्मानित आंकड़ा सिर्फ 'अद्र्धविराम' है। रुककर सोचने, विमर्श करने, रणनीतियां तय करने का समय है। भारत पूरी तरह एक 'खेल-राष्ट्र' बनने का माद्दा रखता है। हम नीरज चोपड़ा जैसा विश्व चैम्पियन खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, तो साबले, श्रीशंकर सरीखे पुरुष खिलाड़ी से लेकर हरमिलन बैंस और वेंकटेश तक की बेटी खिलाडियों को भी तैयार किया है। अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच और प्रशिक्षण मुहैया कराने की जरूरत है। भारत सरकार और राज्य सरकारें इन राष्ट्र-नायकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करें। प्रधानमंत्री मोदी 10 अक्तूबर को अपने आवास पर इन तमाम खिलाडियों से रूबरू मुलाकात करेंगे।

राय

शव संवाद-13

वहां एक सांप मरा था। वर्षों बाद कोई सांप इस तरह मरा था कि देखने वालों को भी बोलने का मौका मिल गया। वह मरने से पहले सांप नहीं था और यह सत्य है कि मरने के बाद ही सांप गिने जाते हैं, इसलिए देखने वालों में उत्सुकता बढ़ रही थी। कोई कह रहा था कि यह कतई नहीं मरता, परंतु इस बार लाठी इससे लंबी हो गई। जो लोग कल तक इस सांप को नजरअंदाज कर रहे थे, आज बेतकल्लुफ इसकी मौत पर अनुसंधान कर रहे थे। मरे हुए लोगों, हारी हुई राजनीतिक पार्टियों, टूटे हुए सपनों, देश के लिए शहीद हो गए लोगों, देश के गुजरे वक्त और अतीत में चले गए प्रधानमंत्रियों पर लगभग उसी तरह का शोध जारी है, जैसे मरे हुए सांप को लेकर देश की जनता इसके कारण ढूंढ रही थी, जैसे पता चल ही जाएगा कि यह धर्म के कारण मरा या इसने कोई देशद्रोह किया। किसी ने कहा कि सांप बहुसंख्यक होते हुए भी क्यों मर रहे हैं, तो किसी ने कहा यह अल्पसंख्यक था, इसलिए इसे चुन कर किसी इनसान ने ही मार दिया होगा। वहां कुछ लोग मूकदर्शक भी थे। ये वही थे जो कोविड काल की गंगा में बहती लाशों पर मूकदर्शक थे और आज भी इलाज के नाम पर किसी अस्पताल से लौटती लाश पर खामोश रहते हैं। ये मान चुके हैं कि इनसान और सांप का मरना एक जैसा संयोग है। जिसका वक्त आएगा वह चुन-चुन कर मारेगा, जिसका जाएगा वह हर किसी के सामने मरता हुआ जाएगा। देश में ये न जिंदा लोगों के साथ हैं और न ही मरे हुए लोगों के साथ, इसलिए सांप का मरना उनके लिए उतना ही अप्रभावशाली था, जिस तरह इसके जिंदा होने पर देश और देश की व्यवस्था को खतरा था। ये ऐसे लोग हैं जो कभी ईश्वर के नाम पर खुशहाल हो जाते हैं, तो कभी किसी नेता के मोहजाल में परम भक्त हो जाते हैं। फिर भी वहां कुछ बेकार हो गए स्वतंत्र पत्रकार, ईडी व इनकम टैक्स के आरोपों से बचे फटेहाल लोग भी थे, जिन्हें विश्वास था कि वे इस सांप की मौत के बाद देश के माहौल को बदल पाएंगे। वे जानते थे या उन्हें विश्वास था कि इस सांप को मरना ही था, क्योंकि भारत की जनता लंबा सोने के बाद जाग गई है। जनता को यह मालूम था कि यह सांप केंचुली बदल-बदल कर स्वांग रच रहा है, जबकि इसे मारने के लिए भीड़ का खौफ ही काफी था। ये वे लोग थे जो देश के हित में हर सांप से बैर रखते हैं, भले ही कोई फन और डंक दिखाए। आश्चर्य यह हुआ कि मरे हुए सांप ने भी जनता को दो गुटों में बांट दिया। यह बिल्कुल राजनीति की तरह होने लगा। एक पक्ष के विचार दूसरे से भिन्न थे। एक गुट के लिए सांप का मरना शुभ था, दूसरे के लिए अशुभ। दूर कहीं से देश का अंतिम बुद्धिजीवी यह नजारा देख खुद को रोक नहीं पाया। उसका इरादा था कि खामख्वाह एक सांप की लाश पर देश की जनता को बेवकूफ होने से बचाया जाए। वह शीघ्रता से लाश को दफनाना चाहता था, लेकिन अब मामला धर्म का हो गया। एक वर्ग इसका दाह संस्कार तो दूसरा दफनाने पर आमादा हो गया। इतना ही नहीं, एक वर्ग इसे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रचार पर उतर आया, जबकि दूसरे ने इसे जहन्नुम में धकेलने के लिए व्हाट्सऐप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह सांप देश की सबसे बड़ी खबर बन गया। एक मशहूर एंकर ने यहां तक कह दिया कि इसे मारने फिर कंस और रावण धरती पर उतर आए हैं, अतः धर्म की रक्षा के लिए इस सांप को फिर से जिंदा करना होगा। सांप के पक्ष में देश के कई चैनल हो गए, मगर बुद्धिजीवी का यू-ट्यूब चैनल खोजने लगा कि कहीं यह सांप मणिपुर में तो नहीं मरा। अब तक बुद्धिजीवी आश्वस्त हो गया था कि यह उसी महल का सांप है, जिसके मालिक स्वयंभू राजा ने देश के सांपों से जहर लिया है। सांप भी राजा के भ्रम में ही मरा है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वह अपने जहर से देश पर राज करेगा। बुद्धिजीवी भले ही इस बार सांप के शव को कंधा नहीं दे सका, लेकिन पहली बार उसकी ही लाठी से यह मरा था।

-क्रमशः

सियासी सीढ़ियों के घुमाव

हिमाचल की राजनीति भी आहिस्ता-आहिस्ता राष्ट्र के सियासी जूते में पांव फंसा रही है या यहां भी सियासत का अपना पूंजीवादी गठबंधन बन रहा है। जिस तरह की चुनाव प्रणाली विकसित हो रही है, उसमें सियासी अस्तित्व के लिए वित्तीय व्यवस्था का सारा तामझाम नई सरमायादारी पैदा कर चुका है। किसी भी चुनाव की सारी सीमाएं व्यय के अंधे कुएं तक पहुंच रही हैं, तो सियासी सीढ़ियों पर चढऩे के लिए एक खजाना या असीमित धन की जरूरत आन पड़ी है। राजनीति के लिए अब जन बाद में, पहले धन आ रहा है और इसीलिए सरकारों का चरित्र बिदक रहा है। कहने को हिमाचल के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाने के लिए हमने बेहतरीन कायदे-कानून बना लिए, लेकिन कार्यान्वयन की मिट्टी पैदा नहीं कर पाए। इसकी वजह यही पूंजीवाद है, जो समाज को राजनीति के समानांतर कमजोर कर रहा है या एक मजबूत गलबहियों में सियासत का अपना व्यापार व दारोमदार दिखाई देता है। ऐसा क्यों संभव हो रहा है कि शिक्षा के सरकारी प्रसार की आंखों के सामने निजी संस्थानों के पौ बारह हो रहे हैं। जब से हिमाचल का चिकित्सा विभाग, मेडिकल कालेजों की ईंटें चुनने लगा है, आम जनता का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में होने लगा है। राजनीति के प्रशंसक एवं प्रवर्तक तो पहले भी व्यापार जगत में होते थे, लेकिन तब ये विचारधारा के लिए निवेश करते थे। अब सियासत किसी विचारधारा से पोषित नहीं, बल्कि पार्टियों के हाशिए विपक्षी दलों से हाथ मिला रहे हैं।

राजनीति अब ओढऩे के बजाय जोड़तोड़ की शक्ति है, जहां हर कोई नेता बनना चाहता है या हर नेता इतना कमा कर रखना चाहता है ताकि चुनावी निवेश में वह कमजोर साबित न हो। इस तरह की एक बहस का प्रदर्शन इस बार हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में भी हुआ, जब एक विधायक ने अपनी बिरादरी को कमाने के लिए असीमित क्षेत्रों के इस्तेमाल का नैतिक सहारा दिया। यानी राजनेताओं द्वारा इस तरह का व्यवसाय अपनाना ऐसा पेशेवर प्रदर्शन है, जहां राजनीति का यह स्वरूप आदर्श व नैतिक है। ऐसे में सत्ता के दम पर राजनीति की तरक्की का हर चेहरा मान्य है और यह देखने को मिल रहा है। हिमाचल में पिछले तीन दशकों से फैल रहे निजी क्षेत्र में ऐसे धंधे फल फूल रहे हैं, जो या तो राज्याश्रित हैं या जिनकी अनुमति प्राप्त करना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मसलन सफल ठेकेदारी, खनन के पट्टे पर क्रशर चलाने की अनुमति, कालेज या प्रोफेशनल शिक्षा संस्थान, पहाड़ छीलने या टीसीपी एक्ट की अंग भंग स्थिति, सरकारी आपूर्तियां तथा नए व्यवसायों की फेहरिस्त में राजनीति की जेब भरती हुई क्यों प्रतीत होती। हद तब होती है जब सत्ता के कार्यक्रमों में लगने वाले शामियाने तक एक तरह की कर वसूली कर जाते हैं। जाहिर तौर पर इससे जनता के स्वभाव व राजनीतिक तंत्र के आगाज में 'खुला खेल फर्रुखाबादी' हो रहा है। यह दो तरफा लाभकारी व्यवसाय है, जहां राजनीतिक संगत में समाज चलने लगा है या समाज को मु_ी में बंद करके रखने की सियासत पर राजकोष जल रहा है।

जिस तरह पेपर लीक की बदनामी में हिमाचल की काबिलीयत गौण हुई, उससे अब कई युवा वाया राजनीति अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। पंचायती निकाय चुनावों में यह देखा गया कि जो युवा करियर बनाने के लिए खून पसीना एक कर रहे थे, वे सभी चुनाव की किश्ती में बैठकर बेरोजगारी के भंवर से बाहर निकलने के लिए, इसी पर भरोसा करने लगे हैं। इन परिस्थितियों में हिमाचल के समाज का गठन ऐसी सियासत पर निर्भर कर रहा है, जो सत्ता में आते ही उनके लिए राहत का कालीन बिछा दे। यही वजह है कि हिमाचल की सत्ता पर कर्मचारी सियासत भारी पड़ रही है या प्रदेश हित में उठाए जाने वाले कदमों के बजाय सार्वजनिक खजाने को बर्बाद करने की मुनादी पिछले कुछ दशकों से हो रही है। राजनीति से सामाजिक भाईचारा इस कद्र है कि टीसीपी जैसे कानून, अतिक्रमण जैसे अपराध और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों पर सरकारों ने आंख और कान पूरी तरह बंद कर रखे हैं। यही वजह भी है कि सामाजिक व राजनीतिक तंत्र का गठजोड़ जनप्रतिनिधि चुनने में आपसी घालमेल कर रहे हैं।

चिंतन विचार

विकास के चुनावी वादों का सच

मुफ्त की सुविधाएं केवल आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ही दी जानी चाहिए'

गत वर्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा-2022 के चुनाव संपन्न हुए। देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी कुछ दलों ने मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन के लक्ष्य को अपना प्रमुख चुनावी वादा बनाया था। राजनीतिक दल आमजन को लुभावने चुनावी नारों के साथ वादों की बरसात करते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य जिनके पास अन्य राज्यों की अपेक्षा सीमित संसाधन हैं, वहां धरातल की सच्चाई जाने बिना इस प्रकार के नारे मात्र हवाई सपने प्रतीत होते हैं। जाहिर है कि इस तरह की चुनावी रेवडियां मतदाताओं को आकर्षित तो करती हैं बल्कि एक हद तक चुनावों में मतदाताओं को किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। सवाल यह है कि क्या यह मुफ्त की राजनीति हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधनों से जूझते राज्य को विकास के स्तर पर किस तरह से प्रभावित करेगी? मुफ्तखोरी की राजनीति भारत में लम्बे समय से विवादों का कारण बनती रही है। हाल के ही दिनों में 'मुफ्तखोरी' शब्द भारतीय राजनीति में विवाद का मुख्य केंद्र बन गया है। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं और श्रमिकों को भत्ता, मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्कूटर, घर आदि के वादों के साथ अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का प्रयत्न करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कई बार मुफ्तखोरी की शॉर्टकट राजनीति के विषय में देश के राजनीतिक दलों से अपील कर चुके हैं। हाल ही में झारखंड के देवघर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को शॉर्टकट वाली सोच से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे शार्ट सर्किट भी हो सकता है और देश बर्बाद हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य को श्रीलंका जैसे देशों में पैदा हुए आर्थिक संकट से जोडक़र भी देखा जा सकता है।

मोदी के इस दावे में काफी हद तक सच्चाई भी दिखती है कि ऐसे राजनीतिक चलन एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए निःसंदेह हानिकारक हैं। ऐसे वादों के साथ चुनी गई सरकारें न केवल करदाताओं के लिए हानिकारक स्थितियां उत्पन्न करती हैं, बल्कि अपने लिए भी समस्याओं को खड़ा करती हैं। सबसे स्याह पक्ष यह है कि इससे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी चुनावों में राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए अभी से ही मुफ्त के वादे शुरू कर दिए हैं, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं हैं। यदि हिमाचल प्रदेश के सन्दर्भ में बात की जाए तो पिछले साल के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने जनता से मुफ्त के कई वादे किए। हालांकि प्रदेश की जनता ने आप पार्टी के दिल्ली के 'मुफ्त मॉडल' को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन इसके बावजूद मुफ्तखोरी की राजनीति हिमाचल प्रदेश के चुनावों में हावी रही थी। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता से इसी प्रकार के कई वादे किए और अंततः प्रदेश में सरकार बनाने में सफल भी हुई! बस में मुफ्त का सफर हो या फिर मुफ्त 320 यूनिट बिजली देने का वादा, फ्रीबीज और इस प्रकार की मुफ्त सुविधाएं देखने-सुनने में तो लुभावनी हैं लेकिन इनका अत्यधिक प्रचार-प्रसार सरकार के बजट में कमी जैसे संकट को बढ़ा भी सकता है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व अन्य विकास कार्यक्रमों, विभागों में धन की कमी का प्रमुख कारण भी बन सकता है। हिमाचल प्रदेश मौजूदा वक्त में जिस त्रासदी से दो-चार हो रहा है, उससे निकलकर वापस विकास की पटरी पर लाना काफी कठिन कार्य होगा। इस प्रकार की मुफ्त सुविधाएं विकास की तमाम अच्छी योजनाओं और कार्यों में और अवरोध पैदा कर सकती हैं। इससे इनके लाभार्थियों में एक प्रकार का निर्भरता सिंड्रोम जन्म लेता है। मुफ्त में प्राप्त वस्तुएं प्राप्तकर्ताओं में निर्भरता और उसकी पात्रता का एक नकारात्मक पैटर्न भी बना सकती हैं, जो भविष्य में पहले से अधिक मुफ्त वस्तुओं की उम्मीद कर सकते हैं। इसके दुष्परिणाम यह होंगे कि उन लोगों में कड़ी मेहनत करने या टैक्स का भुगतान करने के लिए जवाबदेही में कमी आ सकती है। जैसे एक रुपये प्रति किलोग्राम चावल या शून्य लागत पर बिजली जैसी मुफ्त की सुविधाएं लाभार्थियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना को कम कर सकती हैं और उन्हें हर परिस्थिति में बाहरी सहायता पर निर्भर बना सकती हैं।

मुफ्तखोरी पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स ने तमिलनाडु राज्य में एक सर्वेक्षण किया है जिसके अनुसार तमिलनाडु में 41 प्रतिशत मतदाताओं ने मुफ्त की सुविधाओं को मतदान व अपने उम्मीदवार के चयन में एक महत्वपूर्ण कारक माना है। जाहिर है कि इस तरह के वादों से राजकोषीय बोझ व घाटा भी बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, घाटे, ऋण और मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण मुफ्त वस्तुएं मुहैया कराने से राजकोषीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संसाधनों के गलत आवंटन का सबसे सटीक उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मुफ्त में बांटी गयी लैपटॉप योजना है, जिसकी आलोचना नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई लैपटॉप जैसी मुफ्त सुविधाओं ने वहां के स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के कौशल, शिक्षा गुणवत्ता या सीखने के परिणामों में सुधार जैसे अधिक जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका दिया। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को ऐसी सुविधाओं से सचेत होने की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि ऐसी मुफ्त की सुविधाओं से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे पानी, बिजली या ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अति प्रयोग और बर्बादी को बढ़ावा देकर ये एकदम फ्री सेवाएं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी चीजें पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन को कम कर सकती हैं और कार्बन फुटप्रिंट और प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ा सकती हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में किसानों के लिए मुफ्त बिजली के कारण बिजली का अत्यधिक उपयोग और बर्बादी, टैक्स-चोरी जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई है। यहां ध्यातव्य यह है कि हिमाचल प्रदेश का एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है। ऐसे परिवार व युवा वर्ग जो बेरोजगार हों, उनको इन सुविधाओं के दायरे में रखना उचित हो सकता है, मगर सक्षम लोगों को मुफ्त की रेवडियां बांटना ठीक नहीं है।

फैमली के लिए बेस्ट है फ्लॉटर पॉलिसी, नवजात बच्चे के साथ परिवार के 15 लोग हो सकते हैं कवर

परिवहन विशेष न्यूज

हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी होता है। यह एक तरह का सेविंग ही है। इसमें निवेश करके आप खुद के साथ अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने नवजात बच्चे को भी शामिल कर सकते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपको उनके लिए अलग से प्लान लेना होता है। इन पॉलिसी में कब तक बच्चे को कवरेज मिलती है?

नई दिल्ली। आज के समय में मेडिकल के खर्चों को कम करने के लिए और परिवार को सुरक्षित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी कारगर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चों को कवर कर सकते हैं। देश में कई लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व कोविड-19 के वक्त समझ आया। एक हेल्थ इंश्योरेंस में आप खुद के साथ परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप फैमिली फ्लोटर्स पॉलिसी (Family Floater Policy) ले सकते हैं।

फैमिली फ्लोटर्स पॉलिसी कई देशों में मिलती है। इसमें माता-पिता के साथ आप अपने दादा और दादी को भी शामिल कर सकते हैं। वैसे कई एक्सपर्ट का कहना है कि बुजुर्ग माता-पिता को अलग-अलग पॉलिसियों के तहत कवर किया जाना चाहिए। यह काफी अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें फैमिली फ्लोटर्स पॉलिसी से ज्यादा लाभ मिलता है। आइए, पहले जानते हैं कि आखिर आज के समय में हर युवा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों होता है?

हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी

कोई भी दुर्घटना कभी बता कर नहीं आती है। ऐसे में मेडिकल के खर्चों को कवर करने में हेल्थ इंश्योरेंस काफी कारगर साबित होती है। यह आपात स्थिति में पैसों की दिक्कत को भी दूर कर देती है। इसके अलावा इसमें आप खुद के साथ अपनी पत्नी-पति और बच्चे को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें आप और आपकी पत्नी और पति दोनों कवर होते हैं।

अगर आप कहीं बाहर गए हैं तब भी आपको अपने परिवार की चिंता नहीं होगी। अगर आप किसी वर्ष अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद आपका पार्टनर को मेडिकल की आवश्यकता होती है तब भी यह इंश्योरेंस काफी काम आएगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर्स पॉलिसी का लाभ लेते हैं तो यह आपके और पार्टनर के साथ भविष्य होने वाले बच्चे को भी सुरक्षा देता है।

इस पॉलिसी में नवजात शिशु के इलाज के लिए डिलीवरी के 90 दिनों के बाद तक भुगतान किया जाता है। वहीं, लागू प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आपका बच्चा भी इस पॉलिसी में कवर हो जाता है। आइए, जानते हैं कि इस पॉलिसी में नवजात शिशु के कि खर्चों को कवर किया जाता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों में आप 15 व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं।

नवजात शिशु के ये खर्च होते हैं कवर

फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में नवजात बच्चों का पहले 90 दिनों के लिए बीमा किया जाता है। इसमें अगर नवजात बच्चों को किसी भी तरह की कोई मेडिकल परेशानी होती है तो उसे कवर किया जाता है। कई बीमा कंपनी इन पॉलिसी पर एक लिमिट तय करती है। ऐसे में आपको चेक करना चाहिए कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उनके क्या नियम व शर्तें हैं।

कई पॉलिसीहोल्डर मातृत्व लाभ उप-सीमा (Maternity Benefit Sub-Limit) वाले प्लान को सिलेक्ट करते हैं। इसमें मां के साथ शिशु को भी कवर किया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय टीकाकरण में बच्चों को शुरुआत में लगने वाले टीकाकरण का भी लाभ दिया जाता है।

फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों में कब तक शामिल रहता है बच्चा

फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों में बच्चों को 25 उम्र तक शामिल किया जाता है। 25 आयु पूरे होने के बाद बच्चे को फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चे के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना होता है। आपको बता दें कि नवजात शिशुओं को केवल मातृत्व लाभ वाली बीमा पॉलिसियों में ही कवर किया जाता है।

अगर बच्चे की शादी हो जाती है तो उसे पॉलिसी से बाहर कर दिया जाता है। कई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की आयु काफी निर्भर करती है। पॉलिसीहोल्डर की आयु के आधार पर ही प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा पॉलिसीहोल्डर कितनी राशि का कवरेज ले रहा है, यह भी निर्भर करता है।

पॉलिसी में सबसे बड़ा सदस्य जितना बड़ा होगा प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। पॉलिसीहोल्डर जब भी कोई पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं तो उन्हें कई कंपनी की पॉलिसी की तुलना करनी चाहिए। इसके साथ ही कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

गूगल ने भारत में शुरू किया क्रॉमबुक्स का प्रोडक्शन, सीईओ सुदंर पिचाई बोले- छात्रों को मिलेगा फायदा

Google Chromebooks की मैन्यूफैक्चरिंग एचपी की चेन्नई के पास स्थित फ्लैक्स फैसिलिटी में होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए गूगल के सीईओ सुदंर पिचाई ने कहा कि हम एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक्स की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। यह भारत में बनने वाली पहली क्रोमबुक्स होंगी। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कम्प्यूटिंग करना आसान हो जाएगा।

नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पीसी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक्स की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर दी है। एचपी की ओर से ये जानकारी सोमवार को दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, क्रोमबुक्स डिवाइस की मैन्यूफैक्चरिंग एचपी की चेन्नई के पास स्थित फ्लैक्स फैसिलिटी में किया जाना है। जहां कंपनी पहले से ही लैपटॉप और डेस्कटॉप का उत्पादन कर रही है।

सुदंर पिचाई ने किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए गूगल के सीईओ सुदंर पिचाई ने कहा कि हम एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक्स की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। यह भारत में बनने वाली पहली क्रोमबुक्स होंगी। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कम्प्यूटिंग करना आसान हो जाएगा।

HP ने पीएलआई स्कीम के लिए कर चुकी है आवेदन

एचपी उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई 17,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन किया है। एचपी के प्रवक्ता की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि गूगल की क्रोमबुक का उत्पादन भारत में शुरू हो गया है।

दोनों कंपनियों ने संतुक्त बयान किया जारी

गूगल और एचपी की ओर से एक संयुक्त बयान में कहा गया कि क्रोमबुक्स K-12 शिक्षा में एक लीडिंग डिवाइस है। यह पूरी दुनिया में 5 करोड़ छात्रों और शिक्षकों की मदद कर रहा है।

एचपी 2020 से भारत में मैन्यूफैक्चरिंग ऑपरेशन का विस्तार कर रहा है। मौजूदा समय में भारत में P EliteBooks, HP ProBooks, and HP G8 series notebooks का प्रोडक्शन कर रहा है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में आई कमी, नेशनल सैंपल सर्वे ब्यूरो ने जारी किये आंकड़े

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। अप्रैल-जून 2023 के दौरान यह 6 .6 फीसदी रहा जो एक साल पहले 7 .6 प्रतिशत थी। आइए इस रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। नेशनल सैंपल सर्वे ब्यूरो (एनएसएसओ) के लेटेस्ट आकड़ों के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2023 के दौरान घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 7.6 प्रतिशत थी।

देश में पिछले साल अप्रैल-जून की अवधि के दौरान बेरोजगारी अधिक थी, जिसका मुख्य कारण देश में Covid के चलते लगे प्रतिबंध हो सकते हैं। 19वें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) से पता चला कि अप्रैल-जून 2022 में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) 7.6 प्रतिशत थी।

इसके साथ ही जनवरी-मार्च 2023 में बेरोजगारी दर 6.8 फीसदी थी. जुलाई-सितंबर 2022 के साथ-साथ अक्टूबर-दिसंबर 2022 में यह 7.2 प्रतिशत थी। एनएसएसओ के डेटा से पता चला कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2023 में घटकर 9.1 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.5 प्रतिशत थी।

बेरोजगारी दर के आंकड़े

जनवरी-मार्च 2023 में यह 9.2 फीसदी, अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 9.6 फीसदी और जुलाई-सितंबर 2022 में 9.4 फीसदी थी। पुरुषों में, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2023 में गिरकर 5.9 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 7.1 प्रतिशत थी।

जनवरी-मार्च 2023 में यह 6 फीसद, अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 6.5 फीसद और जुलाई-सितंबर 2022 में 6.6 फीसद रही। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सीडब्ल्यूएस (वर्तमान साप्ताहिक स्थिति) में श्रम बल भागीदारी दर अप्रैल-जून 2023 में बढ़कर 48.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 47.5 प्रतिशत थी। बेरोजगार माना जाएगा यदि उसने सप्ताह के दौरान किसी भी दिन एक घंटे के लिए भी काम नहीं किया।

लेबर फोर्स में जनसंख्या के उन सभी को शामिल किया गया है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करते हैं। ऐसे में इसमें नियोजित और बेरोजगार दोनों व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

एनएसएसओ ने अप्रैल 2017 में पीएलएफएस लॉन्च किया था। पीएलएफएस के तहत त्रैमासिक बुलेटिन लेबर फोर्स इंडिकेटर जैसे बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का अनुमान दिया जाता है।

सीडब्ल्यूएस सात दिनों की अवधि में बेरोजगार व्यक्तियों का औसत बताता है। इसके मुताबिक, किसी व्यक्ति को तब बेरोजगार माना जाता है। यदि उसे सप्ताह में एक भी दिन काम न किया हो। वहीं लेबर फोर्स (श्रम बल) सर्वे की तारीख से पहले एक सप्ताह में औसतन नियोजित या बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है। वहीं एलएफपीआर को श्रम बल में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में) अप्रैल-जून 2023 में 45.5 प्रतिशत था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 43.9 प्रतिशत था।

जनवरी-मार्च 2023 में यह 45.2 फीसदी, अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 44.7 फीसदी और जुलाई-सितंबर 2022 में 44.5 फीसदी थी। वर्तमान त्रैमासिक बुलेटिन अप्रैल-जून 2023 तिमाही की श्रृंखला में 19वां है।

सीडब्ल्यूएस के अनुसार श्रम बल, सर्वेक्षण की तारीख से पहले एक सप्ताह में औसतन नियोजित या बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है। एलएफपीआर को श्रम बल में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में) अप्रैल-जून 2023 में 45.5 प्रतिशत था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 43.9 प्रतिशत था।

इस साल जनवरी-मार्च में यह 45.2 फीसदी, अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 44.7 फीसदी और जुलाई-सितंबर 2022 में 44.5 फीसदी थी। वर्तमान त्रैमासिक बुलेटिन अप्रैल-जून 2023 तिमाही की श्रृंखला में 19वां है।

लिस्ट होगा जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर, 37 गुना हुआ था सब्सक्राइब

JSW Infra IPO का शेयर 3 अक्टूबर को लिस्ट होगा।T+2 टाइमलाइन में लिस्ट होने वाला ये दूसरा आईपीओ होगा। इससे पहले केवल आरआर काबेल का ही आईपीओ T+2 टाइमलाइन पर लिस्ट हुआ है। एसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर कर खुला था। इसका इश्यू साइज 2800 करोड़ रुपये का था और ये पूरा फ्रैश इश्यू था।

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर मंगलवार (3 अक्टूबर, 2023) को लिस्ट हो सकता है। T+2 टाइमलाइन में लिस्ट होने वाला ये दूसरा आईपीओ होगा। इससे पहले केवल आरआर काबेल का ही आईपीओ T+2 टाइमलाइन पर लिस्ट हुआ है। बता दें, बाजार नियामक सेबी की ओर से एक सितंबर से आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए T+3 टाइमलाइन को ऐच्छिक रूप से लागू किया है। यह नया नियम एक दिसंबर, 2023 से आईपीओ लाने वाली सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

JSW Infra IPO 37 गुना भरा

जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर कर खुला था। आईपीओ का अलॉटमेंट 28 सितंबर को फाइनल हुआ था।

ये 2800 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू 37.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों के लिए तय किया गया कोटा 10.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी के लिए निर्धारित कोटा 57.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई के लिए रिजर्व कोटा 15.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये पूरा फ्रैश इश्यू है। यानी आईपीओ में मिलने वाला सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 113 रुपये से लेकर 119 रुपये तय किया गया था। इसका लॉट साइज 126 शेयरों का है। जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज (इंडिया), डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार है।

डीमेट अकाउंट में चुटकियों में ऑनलाइन भरें नॉमिनी, फॉलो करें ये प्रोसेस

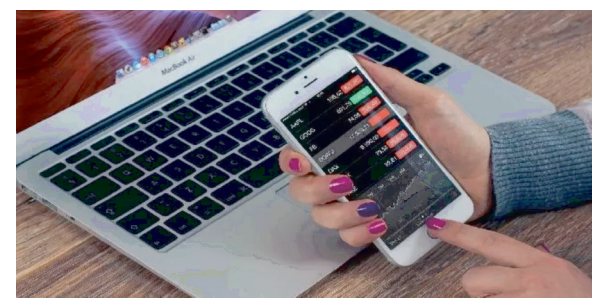

डीमेट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज करना सेबी की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर2023 के बाद आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। डीमैट खाताधारक के परिवार का सदस्य दोस्त या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी नॉमिनी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी अपने डीमैट खाते में दर्ज कर सकते हैं।

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से सभी डीमैट खातों में 31 दिसंबर, 2023 तक नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि अगर डीमैट खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्तियों को आसानी से उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके।

किन खाताधारकों को नॉमिनी भरना अनिवार्य?

वे डीमैट खाताधारक जिनके पास अपना व्यक्ति डीमैट अकाउंट ने उन सभी लोगों के लिए नॉमिनी भरना आवश्यक है। संयुक्त डीमैट खाताधारक भी नॉमिनी भर सकते हैं। हालांकि, गैर-व्यक्तिगत खातों में नॉमिनी भरना संभव नहीं है।

कौन हो सकता है नॉमिनी?

डीमैट खाताधारक के परिवार का सदस्य, दोस्त या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी नॉमिनी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में संपत्ति में अनुपात तय करना होगा।

नॉमिनेशन प्रोसेस

नॉमिनेशन फॉर्म आसानी से आप अपनी डीपी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने डीमैट अकाउंट का नंबर और निजी जानकारी देनी होगी। साथ ही डीमैट खाताधारक को उसका व्यक्ति का नाम, उससे रिश्ता, जन्मतिथि और पता आदि बताना होगा, जिसे वह नॉमिनी बनाना चाहता है। वहीं, अगर नॉमिनी एक से ज्यादा है तो संपत्ति में उनका अनुपात भी तय कर सकते हैं।

ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे भरें?

आप आसानी से डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगा। इसके बाद आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। फिर डीमैट अकाउंट में आपका नॉमिनी दर्ज हो जाएगा।

अपडेट हुई पेट्रोल-डीजल की कीमतें, दिल्ली से मुंबई तक क्या है लेटेस्ट रेट

तेल वितरण कंपनियों की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96 .72 रुपये और डीजल 89 .62 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। ब्रेंट क्रूड 0 .17 प्रतिशत या 0 .16 डॉलर प्रति बैरल बढ़कर 92 .36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें पहले की तरह लगभग सभी बड़े शहरों में समान बनी हुई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आखिरी बार कीमतों में बदलाव 2022 में हुआ था।

नई दिल्ली: पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर
मुंबई :पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई:पेट्रोल 102.74 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर
बड़े महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
नोएडा: पेट्रोल 96.76 रुपये और डीजल 89.93 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम:पेट्रोल 96.97 रुपये और डीजल 89.84 रुपये प्रति लीटर
पटना: पेट्रोल 107.54 रुपये और डीजल 94.32 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ: पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर
जयपुर: पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद: पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

भक्ति को बढ़ाने वाले शास्त्रों के वचनों का निरंतर अध्ययन एवं मनन करना चाहिए : माधव शरण

अनूप कुमार शर्मा

युवा ब्रम्हशक्ति सहित अन्य महिलाओं ने मनाया नंदोत्सव

भीलवाड़ा। शहर के गांधी नगर रोड़ स्थित निंबार्क आश्रम के महन्त एंव ब्रम्हशक्ति मेवाड़ के राष्ट्रीय संरक्षक मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में चल रही संगीतमय भागवत कथा महोत्सव में आज चतुर्थ दिवस के दिन युवा ब्रम्हशक्ति मेवाड़ सहित अन्य महिला मण्डल द्वारा भी नंद महोत्सव मनाया गया। इस दौरान युवा ब्रम्हशक्ति मेवाड़ के एवं निम्बार्क आश्रम के समस्त भक्तजनों के द्वारा कथा व्यास पुजारी माधव शरण का पुष्पमाला पहना सम्मान किया गया।पण्डित नीलेश कुमार पारासर ने बताया कि इस कथा में कथा व्यास माधव शरण ने अपने मुखारविंद से भक्तों को बताया कि भक्ति को बढ़ाने वाले शास्त्रों के वचनों का निरंतर अध्ययन एवं मनन करना चाहिए और वैसा ही कर्म करना चाहिए जो भक्ति को पुष्ट करें क्यों कि कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित्सुख सागरेस्मिन्लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ।।

अर्थात अपार सुखों से युक्त इस संसार सागर में जिसका चित्त परब्रह्म में लीन रहता हैं, उसके कारण उसका कुल पवित्र हो जाता हैं, उसकी माता धन्य हो जाती हैं, और धरती पुण्य से भर जाती हैं, जहां भक्तों द्वारा भक्ति पूर्ण कार्य किया जाता हैं जहां भक्तों द्वारा भक्ति कार्य किया जाता हैं वहा परमानंद ही परमानंद होता हैं।

कथा व्यास माधव शरण ने बताया कि आज के इस चौथे दिन की भागवत कथा दोपहर 3 बजे शुरू हुई जिसमें युवा ब्रम्हशक्ति मेवाड़ की प्रदेशाध्यक्षा नीलम शर्मा एवं गांधी नगर, बसन्त विहार, कांचीपुरम महिला मण्डल के नेतृत्व में महिला शक्ति मण्डल द्वारा सांय 5 बजे नंद महोत्सव मनाया गया।

प्रदेशाध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि कथा के दौरान सांय 5 बजे नंद महोत्सव बड़े ही ठाठबाट और हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन कर नाचते झूमते ऋतुफल, चॉकलेट, ड्राईफ्रूट व अन्य मावे मिष्ठान की मिठाईयों के साथ ही माखन मिश्री का महाभोग लगा प्रसाद वितरण कर मनाया गया।इससे पूर्व प्रातः काल स्थापित सभी देवताओं की अपराजिता, हारश्रिंगार जैसे पुष्पों के साथ चंदन, गुलाल, अबीर से यजमान दिनेश चन्द्र, नीलम शर्मा, शांति लाल अजमेरा, महावीर अजमेरा, रजनीश अजमेरा, ममता अजमेरा, पदमा बाबेल, श्रेयांस बाबेल, गौरव अग्रवाल द्वारा विधिवत पूजाअर्चना भी की गई।

अमृतसर कैबिनेट मंत्री धालीवाल मौके पर पहुंचे और भारतीय प्रवासियों के भूखंडों पर अवैध कब्जे को रोका

अमृतसर (साहिल बेरी) ऑफ अटॉर्नी बनाकर भारतीय प्रवासियों के भूखंडों पर अवैध कब्जे से बचाया। इस संबंध में उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग भारतीय प्रवासियों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गईः धालीवाल ने मौके पर पहुंचकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को बुलाया और तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए. श्री धालीवाल ने कहा कि भारतीय प्रवासी श्री सुदर्शन सिंह, इंग्लैंड से डॉ. गुरदर्शन कौर और कनाडा से रविदर्शन सिंह ने 325 गज के प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए श्री गुरपाल सिंह, रमनदीप कौर और कुछ अन्य लोगों के रूप में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की थी। जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने राजस्व और पुलिस अधिकारियों को साथ लिया। मौके पर ही प्लॉट पर कब्जे के प्रयास को रुकवा दिया गया और फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है. प्रश्नः धालीवाल ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी अप्रवासी की संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं होने देगी. एसः धालीवाल ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबी भाइयों की शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए एक व्हाट्सएप नंबरः 9056009884 भी जारी किया गया है। इस नंबर पर प्राप्त शिकायत संबंधित अधिकारी को भेज दी जाएगी और शिकायत का अपडेट संबंधित पंजाबी प्रवासी को भी दिया जाएगा।

5 राज्यों में चुनाव का बजा बिगुल, नतीजे 3 दिसंबर

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर राजनीतिक दलों के लिए बिगुल बजा दिया है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ में चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर दो चरणों में होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। वहीं तेलंगाना में मतदान 30 नवंबर को होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सोमवार 9 अक्टूबर से पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ विसभा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त हो रहा है। सोमवार को प्रेस कान्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव में 18-19 साल के कुल 60 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। 2900 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर युवा अधिकारी कमान संभालेगें।

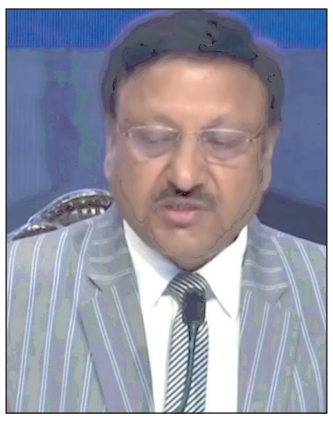

सीजेआई ने कहा कि 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबधित कोई परिवर्तन, विलोपन और संशोधन कराना है तो उसका स्वागत है। वह करा सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांग) पीडब्ल्यूडी के कुल मतदाताओ की संख्या 17.38 लाख है।अगर वह मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर से भी मतदान करने की सुविधा मिलेगी। पांचो राज्यों में आगामी विसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र स्थापित किये जाएगें। 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होगे। 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।और वहीं 8192 केंद्रों पर महिलाए कमान संभालेगी। सीजेआई के मुताबिक इस वक्त पांचों राज्यों की कुल वोटर संख्या 16.14 करोड लाख मतदाता है। इनमें 8.20 करोड पुरूष और 7.8 करोड महिलाए हैं।राजस्थानः नॉमिनेशन 30 अक्टूबर से 6नवंबर, स्क्रूटनी - 7 नवंबर, नाम वापसी-9 मध्य प्रदेश- नॉमिनेशन-21-30 अक्टूबर, स्क्रूटनी-31 अक्टूबर. नाम वापसी-2 नवंबर, वोटिंग-17 नवंबर। छत्तीसगढः- नॉमिनेशन-21-30 अक्टूबर, स्क्रूटनी- 31 अक्टूबर, वोटिंग-7 और 17 नवंबर।

संयुकत तौर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का भंडारी पुल चक्का जाम कर दिया

अमृतसर (साहिल बेरी) अमृतसर के भंडारी पुल पर आज 10:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने भंडारी पुल के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। वाल्मीकि समुदाय के पूर्वक्ताओं ने भाषण में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावो से पूर्व धूना साहिब ट्रस्ट पर मीटिंग के दौरान इस बात का वायदा किया था कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो वह है श्राइन बोर्ड को भंग कर इसकी जिम्मेदारी संत समाज को सौंप देंगे। प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार ने उनसे वायदा खिलाफी कर उनकी कमर में छुरा गोप है। श्राइन बोर्ड भंग करने की बजाय बोर्ड कमेटी में वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय की झाड़ू की नौकरियों पर भी सरकार ने रोस्टर लागू कर इनका रोजगार छीनने की कोशिश की है जिसे वाल्मीकि समाज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा वाल्मीकि समुदाय द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन में सरकार के नुमाइंदे के तौर पर विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारो की लड़ाई लड़ने का हक है उन्होंने कहा कि मैं सरकार का विधायक हूं और मेरी ड्यूटी है कि आपकी मांगों को सरकार के आगे रखूं दूना साहिब ट्रस्ट के चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर ने जहां विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह का धरना स्थल पर पहुंचने पर धन्यवाद किया वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आगामी 11 अक्टूबर तक उनकी मांगों का हल ना किया तो संत समाज 11 अक्टूबर को भंडारी पुल पर पंजाब बंद करने का एलान करेंगे। विधायक को मांग पत्र देने के बाद संत मलकीत नाथ महाराज ने पुल के रास्ते खोलने के निर्देश जारी किए जिस पर भंडारी पुल पर 4 घंटे बाद आवाज आई शुरू हो गई। इस अवसर पर दूना साहिब ट्रस्ट के गद्दी संत मलकीत नाथ, गुरु ज्ञान नाथ आश्रम के गद्दी नशीन संत गिरधारी नाथ, बलवंत नाथ, योगी नाथ, नछत्तर नाथ, महासचिव कमल खोसला, विनोद बिट्टा, सुरेंद्र टोना, सनी सहोता, बाबा बलबीर सिंह गुमटाला, राकेश नाथ, पार्षद बाउ लाल, पार्षद सुरेंद्र भट्टी, राहुल बिल्ला, यशपाल सिद्धू सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे।

प्रवर अधीक्षक डाकघर, अमृतसर मंडल श्री दीपक शर्मा ने प्रेस को सूचित किया कि डाक विभाग

साहिल बेरी

अमृतसर। 9 अक्टूबर, 2023 से 13 अक्टूबर, 2023 तक 'राष्ट्रीय डाक सप्ताह' मनाने जा रहा है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह प्रत्येक 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के साथ शुरू होता है। जब 9 अक्टूबर, 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है। इस वर्ष विश्व डाक दिवस का विषय ₹टुगेदर फॉर ट्रस्ट₹ है।

श्री शर्मा ने प्रेस को बताया कि पूरे राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान अमृतसर मंडल द्वारा विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

10 अक्टूबर, 2023 को वित्तीय सशक्तीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन अमृतसर डिवीजन में प्रत्येक सब डिवीजन द्वारा डाक चौपाल (डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम) का आयोजन किया जाएगा। डाक चौपाल एक व्यापक सामुदायिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जनता को एक ही शिविर में विभिन्न डाक सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। डाक चौपाल में जनता को बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, महिला सम्मान प्रमाण पत्र खोलने, डाक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने और आधार नामांकन और अद्यतनीकरण के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सभी सुविधाएं और सेवाएं ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्र में एक ही छत के नीचे प्रदान की जाएंगी।

11 अक्टूबर, 2023 को फिलाटेली दिवस के रूप में मनाया जाएगा और स्कूलों में ₹न्यू इंडिया फ़ॉर डिजिटल इंडिया₹ विषय पर सेमिनार और प्रश्नोत्तरी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

12 अक्टूबर, 2023 को मेल एवं पार्सल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। थोक और खुदरा ग्राहकों के लिए बैठकें पंजाब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएंगी एवं अमृतसर मंडल में भी ग्राहकों के साथ उक्त बैठकें आयोजित की जायेंगी। ग्राहकों को विभाग की विभिन्न पार्सल और मेल सेवाओं के तहत की गई नई पहलों के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्हें थोक ग्राहकों के लिए पार्सल ट्रैकर की विभिन्न सुविधाओं से

अवगत कराया जाएगा। शुरू से अंत तक ट्रैकिंग, डिलीवरी की अपेक्षित तारीख, रिटर्न पिक अप, सीओडी सुविधा, क्लिक और बुक सेवा, ओटीपी आधारित डिलीवरी आदि।

13 अक्टूबर, 2023 को ₹अंत्योदय दिवस₹ के रूप में मनाया जाएगा। आधार नामांकन और अद्यतनीकरण के लिए ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे जन सुरक्षा योजनाएं, आधार सक्षम भुगतान सेवा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।

श्री दीपक शर्मा ने यह भी बताया कि पंजाब परिमंडल देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार विभिन्न कदम उठा रहा है। विभाग को निर्बाध और विश्वसनीय मेल सेवाएं प्रदान करने के लिए अमृतसर मंडल के दूर दराज इलाकों में डाक पहुँचाने के लिए 05 डाक वाहन लगाये गए हैं एवं पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में एक व्यापक सड़क परिवहन नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसमें 83 मेल वाहन पंजाब के भीतर दिन-रात चलते हैं और पंजाब को दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ के डाकघरों में बुक की गई अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं के परिवहन के लिए लुधियाना से दिल्ली फॉरेन पोस्ट तक एक दैनिक विशेष मेल वाहन शुरू किया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, पंजाब परिमंडल में अंतर्राष्ट्रीय लेखों से राजस्व में 67% की शानदार वृद्धि देखी गई है जो शायद देश में सबसे अधिक है। जनता की मांग के अनुसार पंजाब और चंडीगढ़ के कई डाकघरों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखों के लिए आकर्षक पैकेजिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। राखी सीज़न के दौरान, पंजाब डाक परिमंडल ने भारत और विदेशों में राखियों के सुरक्षित प्रसारण के लिए विशेष राखी लिफाफे और बक्से डिजाइन और आपूर्ति किए। इस पहल के परिणामस्वरूप, अमृतसर मंडल में 16000 से अधिक राखी लिफाफे और बक्से बेचे गए एवं पंजाब परिमंडल में 1.35 लाख से अधिक राखी लिफाफे और बक्से बेचे गए और परिमंडल ने राखी मेल की बुकिंग से लगभग 6 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। साथ ही पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में राखी की शीघ्र डिलीवरी के लिए परिमंडल द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी।

उन्होंने प्रेस को यह भी बताया कि आधार नामांकन और अद्यतनीकरण के लिए पंजाब और चंडीगढ़ के डाकघरों में 498 आधार केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं अमृतसर मंडल में लगभग 7000 आधार (नए/अपडेट) प्रति महीना बनाये जा रहे हैं। निर्यातकों को अपने सामान बुक करने और डाकघर में एक ही काउंटर से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करने के लिए 22 डाक निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमे से 2 डाक निर्यात केंद्र अमृतसर एवं तरनतारन में स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा पंजाब में 09 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं तरनतारन जिले में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए विभाग कार्यवाही कर रहा है। 5 महीने यानी अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 की अवधि के भीतर 51000 से अधिक पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि अगस्त, 2023 में 'हर घर तिरंगा' अभियान के दौरान अमृतसर मंडल द्वारा 27000 झंडे बांटे एवं पंजाब डाक परिमंडल ने पंजाब और चंडीगढ़ में 2.5 लाख झंडे बांटे.अमृतसर मंडल में लगभग 660000 लाइव डाकघर बचत बैंक खाते हैं, जिनमे से 65778 सुकन्या समृद्धि योजना खाते 4297 डाक जीवन बीमा पॉलिसियां और 2289 ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियां हैं एवं पंजाब डाक परिमंडल में लगभग 68 लाख लाइव डाकघर बचत बैंक खाते हैं, जिनमें से 7.37 लाख सुकन्या समृद्धि योजना खाते, 1.02 लाख डाक जीवन बीमा पॉलिसियां और 3.34 लाख ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियां हैं। श्री दीपक शर्मा ने कहा कि इस आधुनिक युग में डाक सुविधाएं केवल मेल सेवाओं तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि भारतीय डाक नागरिकों के जीवन के हर पहलू को छू रहा है। डाकघर जनता की सभी प्रकार की जरूरतों और आवश्यकताओं के लिए सिंगल स्टॉप समाधान और सरकार की डीबीटी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक संवितरण चैनल के रूप में गर्व से उभरा है।

बच्ची को फेंका गया: तीन दिन बाद स्थानीय लोगों ने उसे जिंदा बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया

मनोरंजन सासमल, ओड़शिाभुबनेस्वर : सरकार ने पार्लियामेंट मे महिला बिल पास कर दिया लेकिन लोगों की सोच बदला नहीं ।लड़की एक बोझ समस्ते है । सरकार का नारा{ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ} । जन्म देने के बाद बच्ची को अमानवीय तरीके से झाड़ी की जड़ में फेंक दिया गया, लेकिन ओड़शिा की बालेश्वर जिले सोर शहर के कमरपुर गांव के एक आश्रम मालिक ने उसे बचाया और सोर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार, कमरपुर स्थित अन्नपूर्णा मिल परिसर में बांकबिहारी आश्रम के मालिक त्रैलोक्य दास ने सुबह उठकर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अपनी पत्नी को फोन किया.बाद में उसने बेहद अमानवीय तरीके से बच्ची को झाड़ी की जड़ से बचाया। घायल बच्ची को गर्म पानी से नहलाकर वे उसे अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद, बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे बालासोर जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस सभ्य समाज में आज की घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध रहने पर मजबूर कर दिया है. राय व्यक्त की गई है कि जो भी इस अपराध में शामिल है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

मिशन इंद्र-धनुष द्वितीय रोड का शुभारंभ

अमृतसर।(साहिल बेरी) पंजाब सरकार के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार जी के नेतृत्व में आज से बटाला रोड मेट्रो में मिशन इंद्र-धनुष द्वितीय रोड का शुभारंभ किया गया है। बस स्टैंड। पास की झुग्गियों से बना हुआ। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार ने कहा कि इस मिशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले भर की सभी गर्भवती माताओं और पांच साल के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा और ड्रॉप आउट या छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही टीकाकरण का सारा डेटा यू-विन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर इंटरनेट की सहायता से प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकेगा और टीकाकरण में सुविधा हो सकेगी। इस मौके पर जिला निरीक्षण अधिकारी डॉ. भारती धवन ने बताया कि यह मिशन तीन राउंड में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहला राउंड 11 से 16 सितंबर तक सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दूसरा राउंड आज से शुरू कर दिया गया है, जिसमें पूरे जिले में 9 से 14 अक्टूबर तक कवर किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए अपने सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण कराएं। इस अवसर पर डॉ. इशिता, डॉ. मंजीत सिंह रटौल, डॉ. राघव गुप्ता, डॉ. सुनीत गुरम गुप्ता, जिला एमईआईओ. अमरदीप सिंह एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023